सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 116, नई दिल्ली, शनिवार 05 जुलाई 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है।

03 "बीजेपी ने सरकार बनते ही लिए था पुरानी गाड़ियां को हटाने का फैसला"
06 कक्षाओं में बहुभाषावाद सीखने के परिणामों को बढ़ाएगा
08 पुरी हवाई अड्डे के निर्माण को झटका, वन भूमि अधिग्रहण की मंजूरी स्थगित

दिल्ली में 10 और 15 साल वाले वाहनों को स्क्रैप करने का फैसला वापिस ले लिया गया है : राकेश अग्रवाल (यूनाइटेड फ्रंट फ़ॉर ट्रक ट्रांसपोर्ट एंड सारथी एसोसिएशन)

संजय बाटला

नई दिल्ली। जिस तरीके से महाराष्ट्र के मा.मुख्यमंत्री द्वारा एक जनसभा में महाराष्ट्र RTO बैरियर्स को बंद करने के विषय पर व्यक्तिगत रूप से श्रेय लेने के लिए जल्दबाजी में AIMTC के पदाधिकारियों ने वीडियो जारी करते हुए बताया था कि AIMTC के प्रयासों के कारण ही महाराष्ट्र के RTO बैरियर्स बंद होम जा रहे हैं लेकिन आज तक महाराष्ट्र RTO बैरियर्स पर ट्रक वालो से अवैध वसूली शुरू है और RTO बैरियर्स बंद नही हुए इसी तरीके से दिल्ली में 10/15 साल वाले वाहनों के लिए दिल्ली सरकार ने जो अपना निर्णय वापिस लेने का आदेश किया AIMTC शायद इसका श्रेय भी लेने के लिए सामने आ जाती।

और जिस तरह से महाराष्ट्र में चल रही लोकल ट्रांसपोर्ट संगठनों की हड़ताल में AIMTC के वरिष्ट पदाधिकारी श्री मलकीत बल जी द्वारा दिये गए किसी बयान के कारण उनका व्यापक स्तर पर विरोध हुआ उसको देखते हुए अब AIMTC जल्दबाजी नही करेगी क्योंकि उनको भी ये मालूम पड़ चुका है कि अब इस देश के सभी तरह के ट्रांसपोर्ट व्यबसायी, ड्राइवर्स और बाकी अन्य जनता समझ चुकी है कि AIMTC सिर्फ वाहवाही के चक्कर में जल्दबाजी करते हुए निर्णय ले लेती है और बाद में अन्य संगठनों के विरोध

का सामना करना पड़ता है।

और एक खास बात की जैसे महाराष्ट्र में AIMTC के वरिष्ठ पदाधिकारी मलकीत बल जी जैसे लोग अपने आपको ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का मुखिया समझते हैं वैसे ही AIMTC के चंद राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी अपने आपको ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का मुखिया मानते है और बाकी अन्य ट्रांसपोर्ट से संबंधित संगठनों को अहमियत ना देते हुए कई निर्णय वाहतुकदारों या ड्राइवर्स पर लागू कर देते है जिसका सबसे जीता जागता उदाहरण हिट एंड रन के विरोध में ड्राइवर्स द्वारा की गई सफल हड़ताल को बिना अन्य ट्रांसपोर्ट संगठनों या ड्राइवर्स संगठनों के खत्म करवाने का है और इसके लिए भी उस समय AIMTC का काफी विरोध हुआ था।

ये किसी तरह के आरोप नही हैं लेकिन इस देश के बाकी अन्य सभी ट्रांसपोर्ट संगठनों व किसी भी प्रकार के वाहतूक से संबंधित मालिक, ड्राइवर की मानसिकता बन चुकी है इसलिए AIMTC को अपनी छवि का ख्याल रखते हुए व अपने आपको सभी तरह के ट्रांसपोर्ट से संबंधित विभागों का मुखिया मानते हुए इन सब विषयो को ध्यान में रखना ही होगा क्योंकि इस देश की 140 करोड़ जनता किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी वाहतूक से जुड़ी हुई है।

एक बड़ा सवाल भारत देश के किसी भी क्षेत्र में अपने साथियों को एकजुट कर के और मिलकर परेशानियों से मुक्त करने हेतु जो व्यक्ति विशेष यूनान, संस्था, ट्रस्ट या एनजीओ राज्य सरकार से पंजीकृत करवाकर कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी अन्य पंजीकृत संस्था किस आधार पर निर्णय लेने का दावा कर सकती हैं ?

जैसा की परिवहन क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अपने हक के लिए आवाज उठा रहे पंजीकृत समूह के खिलाफ बयान जारी कर देना, बिन सहमति प्राप्त किया राज्य एवम भारत सरकार को सभी की तरफ से पत्र लिख देना और हास्यप्रद बात तो यह की राज्य एवम भारत सरकार द्वारा भी उसे बिना जांचे मान लेना। *

अगर AIMTC को ही ट्रांसपोर्ट व्यबसाय या देश के बाकी अन्य सभी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट संगठनों के विषय में फाइनल निर्णय लेने का अधिकार है तो भारत सरकार और राज्य सरकार क्यों नहीं ऐसा नियम बना देती कि बिना AIMTC की स्वीकृति या NOC के बिना किस ट्रांसपोर्ट संगठन का रजिस्ट्रेशन ही नही होगा।

क्यो किसी एक पंजीकृत समूह के पत्र के आधार पर भारत एवं राज्य सरकार अनगिनत पंजीकृत समूहों की आवाज को दबा देती हैं, जवाब तो बनता है ?

आपके कमेन्ट और विचारों के इंतजार में

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने कहा

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा उफ़्तसा की ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को खुली चुनौती है कि अपने करोड़ों के बैलेंस शीट व लाखों रुपए चंदे के पैसों से हटकर यदि किसी भी सभा का आयोजन करती है तो चटाई भर बैठने को लोग नहीं जुटेंगे, यह तो पैसों के दम पर विलासिता भरे सभाओं के आयोजन के द्वारा ही एआईएमटीसी कागजों पर जिंदा है यह सिर्फ अपनी-अपनी गाड़ियों को सुविधा पूर्वक चलवाने के लिए एंव एंट्री के खेल को जारी रखने के लिए आम गाड़ी मालिक, सारथीयों व ट्रांसपोर्टरों के भावनाओं से खेल कर सरकार के सामने घुटने के बाल बैठने वाले का नाम ही एआईएमटीसी है। केंद्र व राज्य सरकार भी समय समय पर अपनी-अपनी सुविधाओं की वजह से एआईएमटीसी को ही सुविधा के कारण न्योता देते हैं क्योंकि छोटी बड़ी किसी भी संस्था को खरीद पाना इतना आसान नहीं है उन्हें झुका पाना सरकार के बस में नहीं होता इसके लिए सरकारी प्रतिनिधि के रूप में आज तक एआईएमसीसी काम करती आई है व आज भी कर रही है एंव शत प्रतिशत आगे भी करती रहेगी -आंदोलन का दुर दुर तक इनसे कोई सरोकार नहीं है।

दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 12 स्टेशनों को मिलेगी 'सूरज' की ऊर्जा, 19.54 करोड़ की लागत से लगेगा सोलर पावर प्लांट

दिल्ली मेट्रो रेल निगम फेज चार के दो कॉरिडोर पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा। 19 .54 करोड़ की लागत से 5 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वर्तमान में मेट्रो 51 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न करती है और रीवा संयंत्र से भी बिजली लेती है। इसका लक्ष्य 51 मेगावाट से बढ़ाकर 60 मेगावाट करना है। फेज चार के एलिवेटेड स्टेशनों पर भी संयंत्र लगेंगे जिससे कुल उत्पादन 56 मेगावाट हो जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने फेज चार के दो कॉरिडोर के 12 एलिवेटेड स्टेशनों और शास्त्री पार्क व यमुना बैंक डिपो में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा। 19.54 करोड़ की लागत से ये सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए डीएमआरसी ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह संयंत्र लगने पर पांच मेगावाट बिजली तैयार होगी। इससे दिल्ली मेट्रो में सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति बढ़ेगी।

डीएमआरसी मेट्रो के परिचालन का खर्च कम करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में पहले से ही जुटा हुआ है। यही वजह है कि मौजूदा समय में दिल्ली मेट्रो के 82 एलिवेटेड स्टेशनों व 14 डिपो में सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं। इससे 51 मेगावाट बिजली तैयार हो रही है। इसके अलावा डीएमआरसी को हर वर्ष 345 मिलियन यूनिट बिजली रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र से मिल रही है। इससे डीएमआरसी अभी मेट्रो में बिजली की 33 प्रतिशत जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी कर रहा है।

सौर ऊर्जा का उत्पादन 51 से बढ़ाकर 60 मेगावाट करने का लक्ष्य

डीएमआरसी का कहना है कि फेज चार में अपने स्रोतों से सौर ऊर्जा का उत्पादन 51 मेगावाट से बढ़ाकर 60 मेगावाट करने का लक्ष्य है। इसलिए फेज चार के सभी एलिवेटेड कॉरिडोर पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इसी क्रम में फेज चार में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर पर केशोपुर से दीपाली चौक के बीच, मजलिस पार्क से आरके आश्रम के बीच और तुगलकाबाद-एरोसिटी कॉरिडोर पर साकेत जी ब्लॉक के बीच एलिवेटेड स्टेशनों सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की पहल की गई है। इसके अलावा शास्त्री पार्क व यमुना बैंक में नए भवन की छत पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। साथ ही आरके आश्रम, वसंत कुंज व अंबेडकर नगर स्टेशन के पास बने बिजली के सब स्टेशन में भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। ये संयंत्र लगने के बाद डीएमआरसी अपने सौर ऊर्जा संयंत्रों से कुल 56 मेगावाट बिजली तैयार करने लगेगा।

इन स्टेशनों पर लगेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र

संगम विहार, खानपुर, अंबेडकर नगर, साकेत जी ब्लाक, आजादपुर, अशोक विहार, मंगोलपुरी, वेस्ट एंक्लवे, पुष्पांजलि, केशोपुर, पश्चिम विहार व पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन शामिल है।

ट्रांसपोर्टरों के आंदोलन के दशा व दिशा तय करने पर जोर
ट्रक ट्रांसपोर्टर्स व सारथी संगठनों की एकजुटता का आह्वान

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की बड़ी संस्थाओं के प्रलोभनकारी नीतियों की निंदा

परिवहन विशेष न्यूज

राउरकेला : राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की एक अहम बैठक में देशभर में ट्रक ट्रांसपोर्टर्स और सारथी समाज से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं पर गंभीर चर्चा की गई। इस दौरान देश की तथाकथित सबसे बड़ी व पुरानी संस्था के प्रलोभनकारी व विभाजनकारी प्रयासों पर तीखी आलोचना की गई। बैठक में यह सवाल प्रमुखता से उठा कि सभी संगठनों के नाम पर बुलाई गई मीटिंग को आखिरकार केवल एक संस्था के नाम पर 'आम सभा' के रूप में क्यों प्रचारित किया गया?

बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने दो टूक कहा कि आज वह समय है जब देश के कोने-कोने से उभरती स्थानीय व क्षेत्रीय संस्थाएं ट्रक ट्रांसपोर्टर्स और सारथियों की आवाज बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यदि सभी संगठन अपनी-अपनी प्रतिष्ठा भूलकर एक मंच पर आ जाएं तो केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक को गंभीरता से सुनना पड़ेगा।

'हिट एंड रन' मुद्दे पर दिखाई गई संगठित शक्ति

डॉ. यादव ने कहा कि तथाकथित बड़ी संस्था जहां सरकार से समझौता कर चुकी थी, वहीं राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने देशव्यापी आंदोलन कर इस मुद्दे को पुनर्जीवित किया और उसे एक नई दिशा दी।

महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखे गए सशक्त तर्क

डॉ. यादव ने सवाल उठाया कि जब बीएस-6 मानक वाली गाड़ियां प्रदूषण नियंत्रण में सक्षम हैं, तो फिर उनसे ग्रीन टैक्स क्यों वसूला जा रहा है? उन्होंने स्क्रैप पॉलिसी को 'मोटर कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाला हास्यास्पद निर्णय' करार दिया और सरकार से पूछा कि क्या वह बैटरी चालित वाहनों पर आजीवन फिटनेस की गारंटी एफिडेविट के माध्यम से देने को तैयार है?

रविंद्र बधानी ने जीएसटी और चालान प्रणाली पर उठाए सवाल

प्रमुख ट्रांसपोर्ट नेता रविंद्र बधानी ने सिंगल ट्रक मालिकों को जीएसटी इनपुट की सुविधा देने की मांग की और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में दोहरे जीएसटी ढांचे पर आपत्ति जताई। उन्होंने ऑनलाइन चालान को "प्रशासनिक उत्पीड़न का हथियार" बताते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग रखी।

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने जताया सभी नेताओं का आभार

बैठक में देशभर से सक्रिय ट्रांसपोर्ट संगठनों के निष्ठावान नेताओं की भूमिका की सराहना करते हुए मोर्चा ने विशेष रूप से रविंद्र बधानी, अजय सिंगला, सोमदत्त शर्मा, जरनेल सिंह, राममेहर शर्मा, राधेश्याम मल्लिक, हरदीप सिंह वढेरा, नरेश बंसल, राकेश अग्रवाल, इस्माइल शैयद, सतकुँवर गर्ग आदि सभी नामचीन नेताओं का आभार व्यक्त किया।सभी ने एक स्वर में कहा की संगठित संघर्ष से ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिलेगा न्याय और सम्मान।

अग्निशमन सेवा का बोझ कम कर सकती है दिल्ली सरकार, इस निर्णय से आसान होगा विभाग का काम

दिल्ली सरकार दिल्ली अग्निशमन सेवा को निरीक्षण और एनओसी जारी करने की जिम्मेदारी से मुक्त करने की योजना बना रही है ताकि वे अपने मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। सरकार ने पहले ही कई संस्थानों को लाइसेंस की आवश्यकता से छूट दी है। निरीक्षण का कार्य नगर निगम का है और सरकार इस पर विचार कर रही है।

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार दिल्ली अग्निशमन सेवा को निरीक्षण करने और NOC जारी करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर सकती है। दिल्ली सरकार की ओर से दिशा में निर्णय लेने की योजना बनाई जा रही है, ताकि वे अपने मूल काम अग्निशमन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 30 जून को एक बैठक की थी। प्रमुख योजनाओं, व्यापार करने में आसानी आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की गई थी। इस दौरान उन्होंने कई निर्देश जारी किए। उनमें से एक दिल्ली अग्निशमन सेवा के कार्यभार को कम करने से संबंधित था। दिल्ली सरकार ने हाल ही में स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम को दिल्ली पुलिस द्वारा लाइसेंस की आवश्यकता से छूट देकर लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया है। अधिकारी ने कहा कि इसी तरह हम निरीक्षण और एनओसी जारी करने के काम को हटाकर दिल्ली अग्निशमन सेवा के लिए काम को सरल बनाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण करना नगर निगम का काम है। हम इसके लिए एक प्रस्ताव पर चर्चा और काम कर रहे हैं।

उम्र के आधार पर वाहनों पर प्रतिबंध सही नहीं, ईंधन व उत्सर्जन मानकों में सुधार की जरूरत; एक्सपर्ट ने दिए सुझाव

परिवहन विशेष न्यूज

सीएसई ने उम्र के आधार पर वाहनों को हटाने का समर्थन नहीं किया है बल्कि ईंधन और उत्सर्जन मानकों में सुधार का सुझाव दिया है। सीएसई ने प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को सुधारने की वकालत की है। ग्रीन एक्टिविस्ट भावरीन कंधारी ने नो-फ्यूल पॉलिसी को परेशान करने वाली बताया है। सीएसई ने उम्रदराज वाहनों के लिए मानक तय करने और पीयूसी सिस्टम को सुदृढ़ करने का सुझाव दिया है।

नई दिल्ली : राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के वास्तविक कारणों पर वैज्ञानिकों और पर्यावरण नीति विशेषज्ञों के बीच बहस तेज हो गई है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने कहा कि वह उम्र के आधार पर वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश नहीं करता हैं। ईंधन व उत्सर्जन मानकों में सुधार करने की सलाह दी है।

आईआईटी दिल्ली और दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के साथ सीएसई के विशेषज्ञों ने पीयूसी व्यवस्था में सुधार की वकालत की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क पर वाहनों का रखरखाव ठीक से हो।

ईंधन और उत्सर्जन मानकों में सुधार की सिफारिश की: सुनीता

सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण का कहना है कि स्वच्छ हवा के अधिकार पर अपने दशकों लंबे अभियान में, सीएसई ने कभी भी पुराने वाहनों को बंद करने की सिफारिश नहीं की है।

इसके बजाय, हमने वाहनों के लिए ईंधन और उत्सर्जन मानकों में सुधार की सिफारिश की है। इसमें 1990 के दशक के मध्य में बीएस-0 से लेकर 2020 में बीएस-6 की शुरुआत तक शामिल है।

हालांकि, कुछ अन्य विशेषज्ञों ने बताया कि वाहन की आयु उच्च उत्सर्जन की संभावना पर एक निर्णायक कारक है। सीएसई ने कहा, यह सही है कि गाड़ियां जिसमें निजी गाड़ियां भी शामिल है हवा को काफी अधिक प्रदूषित कर रही हैं।

सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की बात की

इसी वजह से हम हमेशा सार्वजनिक परिवहन और मोबिलिटी सिस्टम को मजबूत करने की बात हमेशा करते रहे हैं। निजी गाड़ियों को कम करने के लिए पार्किंग रेट बढ़ाने, पार्किंग मैनेजमेंट एरिया प्लान बनाने जरूरी है।

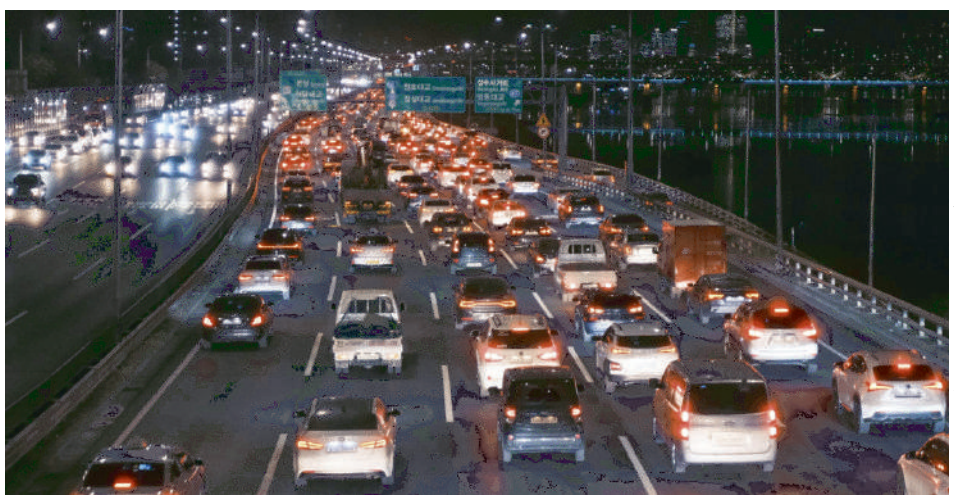

उन्होंने कहा कि गाड़ियों को स्क्रैप करने और उसकी फ्लीट रिन्यूल का सुझाव कमर्शियल वाहनों जैसे ट्रक आदि पर सही है। लेकिन इसमें भी कमर्शियल वाहन मालिक को अपनी गाड़ी बदलने पर इंसेंटिव आदि दिया जाना चाहिए।

आईआईटी दिल्ली में परिवहन अनुसंधान और इंजरी प्रिवेंशन सेंटर की सहायक प्रोफेसर दीप्ति जैन ने कहा कि किसी वाहन का टेल-पाइप उत्सर्जन वाहन की आयु, मेक, मॉडल, चलाए गए किमी और फिटनेस पर निर्भर करता है।

उन्होंने कहा कि यदि वार्षिक औसत किमी अधिक है तो कोई यह उम्मीद कर सकता है कि प्रति किमी औसत उत्सर्जन नए वाहनों की तुलना में अधिक होगा। उन्होंने कहा कि उत्सर्जन करने वाले वाहनों को छोड़ने के लिए आयु एक मानक बन जाती है।

जैन ने कहा कि समस्या यह है कि वाहनों के लिए एक आधार रेखा निर्धारित की जानी चाहिए। पीयूसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, साथ ही फिटनेस प्रमाणपत्र भी।

नो-फ्यूल पॉलिसी "परेशान करने वाली"

ग्रीन एक्टिविस्ट भावरीन कंधारी का कहना है कि नो-फ्यूल पॉलिसी "परेशान करने वाली" है। यह पालिसी लोगों को पुरानी कारों को स्क्रैप करने और नई खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है।

इससे सड़क पर वाहनों की कुल संख्या बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा नए वाहनों से नहीं आएगी बल्कि यह कम वाहनों से आएगी।

उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि प्राइवेट कार पर निर्भरता कम करने पर ध्यान केंद्रित करना है। कंधारी ने कहा कि उम्र आधारित प्रतिबंध वास्तविक दुनिया के उत्सर्जन को अनदेखा करते हैं।

एक पुरानी अच्छी तरह से रखरखाव की गई कार नए, खराब रखरखाव वाले वाहनों की तुलना में कम उत्सर्जन कर सकती है।

सीएसई की ओर से दिए गए सुझाव

राज्य और राष्ट्रीय नीति के आधार पर उम्रदराज वाहनों के लिए तय किए जाएं मानक।

ऑटोमेटेड और एडवांस्ड व्हीकल टेंस्टिग सिस्टम और वाहनों की पहचान कर अनफिट करार दें।

गाड़ी कितना प्रदूषण कर रही है, इसके लिए रिमोट सेंसिग मॉनीटरिंग अपनाई जाए।

वाहनों को फेजआउट करने के लिए इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव दिए जाएं।

पीयूसी सिस्टम सुदृढ़ हो और इसका एनफोर्समेंट भी प्रभावी हो।

दिल्ली समेत सभी राज्य अनफिट और उम्र पूरी कर चुके वाहनों की सूची जारी करें।

अनफिट व उम्र पूरी कर चुके वाहनों की जांच को बने ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर

शाम को वाहनों की औसत रफ्तार हो जाती है कम

ट्रैफिक जाम भी राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता को खराब करने का कारण बनता है। सीएसई के डेटा से पता चला है कि शाम 5 से रात 9 बजे के बीच ट्रैफिक की औसत रफ्तार 15 किमी प्रति घंटे तक कम हो जाती है।

जबकि लगभग इसी समय, एनओ2 का स्तर दोपहर 12 से सायं 4 बजे के बीच, जब ट्रैफिक की औसत रफ्तार 21 किमी प्रति घंटा होती है, की तुलना में 2.3 गुना ज्यादा होता है।

आशा दशमी आज

आशा दशमी व्रत पारंपरिक हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष के दौरान मनाया जाता है। उत्तर भारत में आशा दशमी 2025 की तिथि 5 जुलाई है। इस दिन की रस्में देवी पार्वती को समर्पित हैं और यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में यह अनुष्ठान गिरिजा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पूजा और अनुष्ठान देवी पार्वती को समर्पित होते हैं। यह व्रत शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

आशा दशमी व्रत

आशा दशमी व्रत हिंदू धर्म में, विशेष रूप से उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। ₹आशा₹ शब्द आशा या इच्छा को दर्शाता है, और ₹दशमी₹ चंद्र पखवाड़े के दसवें दिन को संदर्भित करता है। इसलिए, आशा दशमी व्रत इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए समर्पित एक दिन है, जिसमें देवी पार्वती के आशीर्वाद को प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जो शक्ति, भक्ति और वैवाहिक सद्भाव का प्रतीक हैं।

समय और महत्व

आशा दशमी व्रत हिंदू चंद्र कैलेंडर में आषाढ़ महीने के दौरान शुक्ल पक्ष (चंद्रमा के बढ़ते चरण) के 10 वें दिन (दशमी) को मनाया जाता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में जून या जुलाई में पड़ता है।

यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं, विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की भलाई और दीर्घायु के साथ-साथ अपने परिवार की समृद्धि के लिए देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अविवाहित महिलाएं भी देवी पार्वती की भक्ति और गुणों को दर्शाते हुए उपयुक्त जीवनसाथी पाने के लिए यह व्रत रख सकती हैं।

रस्में देवी पार्वती की पूजा पर केंद्रित

आशा दशमी व्रत की रस्में देवी पार्वती की पूजा के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं। दिन की शुरुआत सुबह जल्दी स्नान से होती है, उसके बाद प्रार्थना क्षेत्र की सफाई और सजावट की जाती है। भक्त अक्सर देवी पार्वती की मूर्ति या छवि के साथ एक छोटी वेदी बनाते हैं।

प्रमुख अनुष्ठान

संकल्प : भक्त समर्पण और ईमानदारी के साथ व्रत का पालन करने का संकल्प लेता है।

पूजा : एक विस्तृत पूजा (अनुष्ठान पूजा) की जाती है, जिसमें देवी को फूल, धूप, फल और मिठाई अर्पित की जाती है। भक्त देवी पार्वती के लिए विशेष मंत्र और प्रार्थनाएँ पढ़ते हैं, और उनसे आशीर्वाद माँगते हैं।

उपवास : उपवास इस व्रत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भक्त या तो भोजन और पानी के बिना सख्त उपवास (निर्जला व्रत) रखते हैं या केवल फल और दूध का सेवन करके आंशिक उपवास करते हैं।

व्रत कथा

आशा दशमी से जुड़ी व्रत कथा या कहानी पूजा के दौरान सुनाई या सुनी जाती है। यह कहानी आमतौर पर देवी पार्वती के गुणों और भगवान शिव के प्रति उनके समर्पण को उजागर करती है, जो भक्तों के लिए प्रेरणा का काम करती है।

व्रत तोड़ना : व्रत आमतौर पर शाम को अनुष्ठान पूरा होने के बाद तोड़ा जाता है और देवी को प्रसाद चढ़ाया जाता है।

आधुनिक समय की प्रासंगिकता

समकालीन समय में, आशा दशमी व्रत हिंदू महिलाओं के बीच एक पूजनीय परंपरा बनी हुई है, जो उनकी अटूट आस्था और भक्ति का प्रतीक है। जबकि मुख्य अनुष्ठान अपरिवर्तित रहते हैं, व्रत के आध्यात्मिक और भावनात्मक पहलुओं पर जोर बढ़ रहा है, जो आंतरिक शांति, मानसिक शक्ति और परिवार की भलाई पर केंद्रित है।

जैसे-जैसे समाज विकसित होता है, व्रत सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक बंधनों के महत्व की याद दिलाने का काम भी करता है। कई महिलाएं व्रत रखने में सांत्वना और शक्ति पाती हैं, इसे व्यक्तिगत चिंतन और आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में देखती हैं।

नकली दूध को कैसे पहचानें, जानें मिलावट को जांचने का सटीक तरीका

1 दूध में पानी की जांच- सबसे पहले दूध में पानी की मिलावट को परखने के लिए किसी लकड़ी या पत्थर पर दूध की एक या दो बूंद गिराइए। अगर दूध बहकर नीचे की तरफ गिरे और सफेद निशान बन जाए तो दूध पूरी तरह से शुद्ध है।

2 दूध में डिटर्जेंट- दूध में डिटर्जेंट की मिलावट को पहचानने के लिए, दूध की कुछ मात्रा को एक कांच की शीशी में लेकर जोर से हिलाइए। अगर दूध में झाग निकलने लगे तो इस दूध में डिटर्जेंट मिला हुआ है। अगर यह झाग देर तक बना रहे, तो दूध के नकली होने में कोई संशय नही है।

3 दूध में यूरिया की पहचान- सिंथेटिक दूध में अगर यूरिया मिला हुआ है, तो वह गाढ़े पीले रंग का हो जाता है।

4 असली और नकली दूध की पहचान- स्वाद के मामले में असली दूध हल्का-सा मीठा स्वाद लिए हुए होता है, जबकि नकली दूध का स्वाद डिटर्जेंट और सोडा मिला होने की वजह से कड़वा हो जाता है।

5 नकली दूध कैसे पहचानें- दूध को देर तक रखने पर, असली दूध अपना रंग नहीं बदलता है। जबकि दूध अगर नकली है, तो वह कुछ समय बाद पीला पड़ने लगेगा।

6 असली दूध की पहचान- असली दूध को उबालने पर उसका रंग बिल्कुल नहीं बदलेगा, लेकिन नकली दूध का रंग उबलने पर पीला हो जाएगा।

7 दूध की गंध- दूध को सूंघकर देखें। अगर दूध नकली है, तो उसमें साबुन की तरह गंध आएगी और अगर दूध असली है, तो उसमें इस तरह की गंध नहीं आती

अध्यात्म व्यक्ति के कुछ जीवन उपयोगी कुछ संदेश

नंबर 1:-
अपने जीवन में ईमानदार रहे।

नंबर 2:-
अपने रोजी-रोटी खुद कमाए।

नंबर 3:-
अपने कर्तव्यों का पालन परमात्मा की ड्यूटी समझकर करें।

नंबर 4:-
किसी का हक दबाने की कोशिश ना करें।

नंबर 5:-
कथनी करनी रहनी को एक जैसा रखें विचार ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं, अपने विचारों को सदा शुद्ध रखें।

नंबर 6:-
कर्म के सिद्धांत को कोई नहीं बदल सकता परमात्मा भी नहीं तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का परिणाम है

नंबर 7:-
जो जैसा इस पृथ्वी पर कर्म करता है, उसके अनुसार ही तुम्हारा जीवन बनता भी है।

नंबर 8:-
सत्संग कोई जादू नहीं तुम्हारे जीवन रूपांतरण की प्रक्रिया है, ताकि तुम समझ कर अपने जीवन का कल्याण कर सको।

नंबर 9:-
यदि तुम्हारी जिंदगी अमली नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता तुम्हें शांति नहीं मिलेगी।

नंबर 10:-
दूसरे के लिए किया गया कर्म स्वयं का जीवनका बीजारोपण है वापस वही मिलता है, जो तुम दूसरों के लिए करते हो प्रकृति में कुछ गलत है ही नहीं तुम्हारा ही तुम्हें अर्पण है।

नंबर 11:-
ध्यान प्रेम के अलावा कोई मार्ग नहीं है, ध्यान तुम्हें स्वयं आत्मा से जोड़कर परमात्मा की और पूर्ण रूपांतरण कर देता है।

नंबर 12:-
ध्यान कोई चमत्कार नहीं है। ध्यान में तुम स्वयं से जुड़ने हो।

नंबर13:-
ध्यान में अगर तुम्हें यह समझ नहीं है, ध्यान क्या तो ध्यान का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर नहीं पड़ेगा ध्यान जागृति है, ताकि तुम बात को समझ कर अध्यात्म में परिपूर्णता को हासिल कर सको जहां पर हमें विश्राम और शांति है।

नंबर14:-
जीवन की खोज अध्यात्म की खोज है।

नंबर 15:-
वास्तविक धर्म मनुष्यता है, जियो और जीने दो मनुष्य बनो।

नंबर 16:-
हर इंसान अपने लिए वही चाहता है, जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन वह नहीं करता जो दूसरे को अच्छा लगता है।

नंबर17:-
दूसरे की भावनाओं को समझ कर उसको समझाना यही मानवता है।

नंबर 18:-
तुम नहीं जानते तुम्हारे मन के भीतर कितना द्वंद्व चलता है, जो तुम्हारे जीवन को ध्वस्त कर देगा।

नंबर 19:-
अपने मन को स्वच्छ करें ताकि वहां शुद्ध तुम्हारा स्वरूप प्रकट हो सके।

नंबर 20:-
यदि तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, दौलत तुम्हारा ज्ञान किसी के काम का नहीं जब तक वह तुम्हारे जीवन में अमल नहीं है।

जितना तुम जानते हो उतना ही कहो जितना तुम प्रैक्टिकल हो।

- जो क्रोधमें आकर अथवा किसी बातसे दु:खी होकर आत्महत्या कर लेता है, वह दुर्गतिमें चला जाता है अर्थात भूत-प्रेत-पिशाच बन जाता है। आत्महत्या करनेवाला महापापी होता है। कारण कि यह मनुष्यशरीर भगवत्प्राप्तिके लिये ही मिला है;
- अत: भगवत्प्राप्ति न करके अपने ही हाथसे मनुष्यशरीरको खो देना बड़ा भारी पाप है, अपराध है, दुराचार है। दुराचारीकी सद्गति कैसे होगी ? अत: मनुष्यको कभी भी आत्महत्या करनेका विचार मनमें नहीं आने देना चाहिये।
- मनुष्यपर कोई बड़ी भारी आफत आ जाय, कोई भयंकर रोग हो जाय, तो वह यही सोचता है कि अगर मैं मर जाऊँ तो सब कष्ट मिट जायँगे। परन्तु वास्तवमें आत्महत्या करनेपर कर्मोंका भोग (कष्ट) समाप्त नहीं होता, उसको तो किसी-न- किसी योनिमें भोगना ही पड़ेगा।
- आत्महत्या करके वह एक नया पापकर्म करता है, जिसके फलस्वरूप उसको नीच योनिमें जाना पड़ेगा, भूत-प्रेत बनना पड़ेगा और हजारों वर्षोंतक दु:ख पाना पड़ेगा।

प्रश्न आया है कि कैसे कोई पुरुष, घर में अपनी माता और पत्नी में सामंजस्य स्थापित करें? बहुत ही सटीक और व्यवहारिक प्रश्न है।

हर घर में यह घटना अपनी-अपनी तरह से विकराल रूप धारण करती जा रही है। माता और पत्नी के मध्य एक 'सेतु' है जो एक का बेटा है और दूसरे का पति है। माता गर्भ से ही, पालने से ही अपने पुत्र के लिए भविष्य के स्वप्न संजोती है और वहीं पत्नी अपने भविष्य में एक नेहरूपी सहचर की कल्पना में रहती है। दोनों ही उससे प्रेम/नेह रखतीं हैं। लेकिन विवाह होते ही बेटे का आकर्षण, थोड़ा-सा पत्नी की तरफ झुकते ही, माता असुरक्षित हो जाती है। और नवविवाहिता/पत्नी अपने सहचर/साथी/पति पर किसी और स्त्री का अधिकार, भले वह उसकी जन्मदात्री ही क्यों न हो? देखकर असुरक्षा से भर जाती है। यह दोनों सिरे इसी एक पुरुष से जुड़ें हैं लेकिन उनकी भावना से पूरी तरह 'अनभिज्ञ' पुरुष, कभी इधर ज्यादा और कभी उधर ज्यादा झुक जाता है। यह तो हुई समस्या की जड़ की बात। अब आते हैं समाधान की तरफ। माता, अपने गर्भ/गोद से जुड़े बच्चे को, अपने से दूर-दूर या किसी दूसरी स्त्री, भले जिसे वह स्वयं अरमानों से ब्याह कर घर लाती हो या कभी बेटे की पसंद पर हामी भरी हो, के संपर्क में होना भीतर बर्दाश्त नहीं कर पाती, यह स्त्री जनित स्वाभाविक ईर्ष्या है लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी माता अपने बेटे का जीवन बर्बाद करने को राजी नहीं होगी, यदि उसे जगा दिया जाये। इसी प्रकार पत्नी भी, अपने पति को दो स्त्रियों की रस्साकसी में, सुलगते/उलझते/टूटते नहीं देख सकती, यदि वह उसे पसंद करती हैं, नेह रखतीं हैं। यह वास्तविकता जानते ही वह मध्य सूत्र, यानि पुरुष की सूझबूझ बहुत महत्व रखती है जिसमें बिना दोनों को हर्ट किये, बिना शोरगुल के वह इस समस्या का समाधान करके अपने घर/परिवार/बच्चों/संसार के साथ-साथ विशेषकर अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। संबंधित ने कहा कि मेरा दिल करता है कि 'सब छोड़-छाड़कर कहीं चला जाऊं।' ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि आप माता की गोद में सिर रखकर, बिना उन दोनों पर तीखे आरोप-प्रत्यारोप किये, धीरे से अकेले में अपनी पीड़ा बता दें कि 'माता-पत्नी की खींचातानी में मैं घुट गया हूं' तो पुत्र का ऐसा साथ-सम्पर्क-संवाद, पाकर वह माता अपनी सारी असुरक्षा ताक पर रखकर, उसके सुखद जीवन के लिए, अपने पुत्र-पुत्रवधू पर 'आक्षेप/दोषारोपण' करना बंद कर देगी। इससे एक तरफ की खींचातानी थोड़ी कम हो जायेगी। अब नेह से भरी पत्नी, जो पति का परिवार देख-सुनकर ही विवाह के लिए तैयार हुई थी, को, यदि उचित साथ-स्पर्श के साथ अपने मन की 'वही' बात बताई जाये, बिना किसी जोर-जबरदस्ती/दबाव बनाते हुए, कि मैं बिना परिवार के, जड़-मूल के कटा वृक्ष/तना मात्र रह जाऊंगा, और मेरी जीवनेच्छा मरती जा रही है। तो नेहपूरित कोई भी पत्नी, अपने सहचर को विक्षिप्तता/डिप्रैशन/रोग/पीड़ा में जाता नहीं देख सकती और अपने स्तर/लैवल पर घर की सुख-शांति के लिए, सास के साथ सामंजस्य स्थापित करने लगेगी। माता और पत्नी, यह दोनों जिस पुरुष से जुड़ी हैं, यदि उन दोनों को, अपने-अपने स्तर पर नेह का अहसास मिलने लगे तो उनकी असुरक्षा विलीन/निरसित हो जायेगी। और यही दोनों मिलकर, उसी मध्य सूत्र (पुरुष के) सुख-स्वास्थ्य के लिए अपने-अपने कदम बढ़ाने/उठाने में सहर्ष तैयार हो जायेंगीं।

जब युधिष्ठिर का अहंकार टूटा

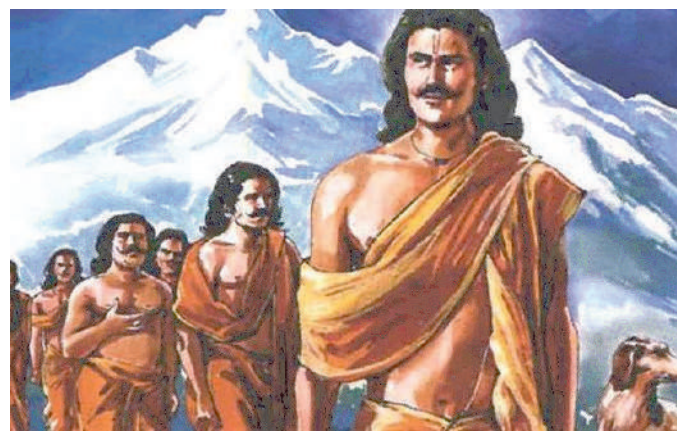

महाराज युधिष्ठिर का संकल्प था कि वे अपनी प्रजा को सदा दान देते रहते थे उनके पास अक्षयपात्र था जिस की विशेषता यह थी कि उससे जो भी मांगा जाए तुरन्त प्रस्तुत कर देता था युधिष्ठिर अपने दान के बल पर शिवि, दधिचि और हरिश्चंद्र को भी पीछे छोड़ देना चाहते थे।

उनके राजमहल में सोलह हजार आठ ब्राह्मण नित्य उपस्थित होते और उन्हें भोजन के साथ-साथ दान दिया जाता था।

भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के इस दम्भ को पकड़ लिया और उन्हें घूमाने के बहाने पाताल लोक के स्वामी बलि के पास ले गए बली ने बड़े आदर से भगवान कृष्ण तथा युधिष्ठिर की अभ्यर्थना की तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर संकेत करते हुए पूछा की असुर राज बली क्या आप इन्हें जानते हैं ?

बलि ने कहा नही मैं इनसे पहले से परिचित नहीं हूँ।

श्री कृष्ण ने कहा कि ये पाण्डवों के ज्येष्ठ महादानी युधिष्ठिर है इनके द्वारा किये दान से पृथ्वी का कोई व्यक्ति वंचित नहीं है और आज पृथ्वी वासी तुम्हें तो याद भी नहीं करते।

बलि ने विनित हो भगवान को प्रणाम किया और मुस्कुरा कर बोले कि महाराज मैंने तो कोई दान नहीं किया मैंने तो वामन देव को मात्र तीन पग भूमि दी थी।

श्री कृष्ण ने कहा कि किन्तु बलि भारतखण्ड में प्रजा युधिष्ठिर के सिवा सभी दानवीरों को भूल गई है।

बलि के चेहरे पर तनिक भी ईर्ष्या नहीं दिखी उन्होंने कहा कि प्रभु यह तो कालचक्र है वर्तमान के सामने अतीत धुंधला पड़ ही जाता है और वर्तमान सदैव वैभवशाली होता है ; मुझे प्रसन्नता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने दान बल से मेरी कथाएँ बंद कर दी हैं मैं धर्मराज का दर्शन कर कृतार्थ हुआ।

श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि इनके पास एक अक्षय पात्र है जिससे ये प्रतिदिन 16008 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तथा मुँह मांगा दान देते हैं जिससे इनकी जयजयकार होती है।

राजा बलि ने चौंकते हुए कहा प्रभु आप इसे दान कहते हैं ! यदि यह दान है तो पाप क्या है.....

हे पाण्डव श्रेष्ठ आप ब्राह्मणों को भोजन देकर अकर्मण्य बना रहे हैं तब तो आपकी प्रजा को अध्ययन अध्यापन, यज्ञ, अग्नि होत्र आदि कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। केवल अपने दान के दम्भ को बल देने के लिए कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को आलसी बनाना पाप है।

मैं इसकी अपेक्षा मर जाना उचित मानता हूँ।

भगवान श्रीकृष्ण ने प्रश्न किया असुरराज क्या आपके राज्य में दान नहीं दिया जाता या प्रजा आपसे दान मांगने नहीं आती ?

बलि ने कहा कि यदि मैं अपने राज्य के किसी याचक को तीनों लोगों का स्वामी बना दूँ तो भी वह प्रतिदिन अकर्मण्य होकर मेरा दिया भोजन स्वीकार करने नहीं आएगा मेरी राज्य में ब्राह्मण कर्म योग के उपासक हैं।

प्रजा कल्याण साधन किए बिना कोई दान स्वीकार नहीं करती

आपके प्रिय धर्मराज जी जो दान कर रहे हैं उससे कर्म और पुरुषार्थ की हानि हो रही है।

भगवान श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर की ओर देखा युधिष्ठिर को अपनी भूल का ज्ञान हो चुका था, उन्होंने अपना सर झुका लिया

'विषय - रुपयों का संग्रह, खर्च और त्याग।'

समय को कीमती नहीं समझा। रुपयों को कीमती समझा है। समय देकर रुपया खरीदा जा सकता है। रुपया देकर समय नहीं खरीदा जाता। अगर रुपयों से समय खरीदा जाता तो धनी आदमी नहीं मरते। इससे सिद्ध होता है कि रुपयों से समय कीमती है।

दान देने से लोगों को सहायता मिलती है, उपकार होता है, धन का महत्व है, रुपयों के द्वारा उपकार हुआ तो रुपयों के कारण हुआ, तो रुपया बेठीक कैसे हुआ ? यह प्रश्न है।

स्वामी जी - रुपयों के द्वारा उपकार समझना है तो रुपयों का लोभ होता है। जबकि महत्व भगवान का है। रुपयों के द्वारा उपकार होता है, रोगी को दवाई मिल जाती है, असहाय को सहायता मिल जाएगी, तो यह भौतिक लाभ ही तो हुआ। कल्याण कहां हुआ ! दुःख कहां मिटा ! शांति कहां मिली ! भगवान की तरफ रुचि करा देना बहुत महत्व की बात है। रुपयों का महत्व समझने से संसार का ही महत्व होगा। शास्त्रों में आया है कि दान करने के लिए भी रुपया कमाने की जरूरत नहीं है। कादा लगाकर धोना बढ़िया है क्या ? जितना कादा लगाया है, उतना ही पानी से कादा साफ हो जाएगा क्या ? दस गुना पानी चाहिए, तब कादा साफ होगा। रुपया कमाने से जो पाप, अन्याय कमाया है, वो साथ जाएगा। पाप, अन्याय अंतःकरण में अंकित हो गया और रुपया साथ जाएगा नहीं। चोर चोरी करता है तो कमाया हुआ रुपया चोरी करता है। अंतःकरण में अंकित झूठ, अन्याय की चोरी नहीं करता। रुपयों से रद्दी चीज कोई है ही नहीं। विष्ठा भी खुद काम आती है (सूअर आदि खाते हैं) रूपया खुद क्या काम आता है ? रुपयों के कारण बड़े-बड़े पाप करता है। संतति निरोध करता है। बच्चे पैदा नहीं करता है। मैं दान को बुरा नहीं समझता हूं। पर दोनों - दान और कल्याण को मिलाकर देखा जाए तो कल्याण श्रेष्ठ है। जड़ता से जड़ता की सेवा करके त्याग करके कल्याण करना श्रेष्ठ है। मानो रुपयों का त्याग (दान) रूपयों से संबंध विच्छेद होने का लाभ है। रुपयों का लाभ नहीं है। जिससे महान सुख हो जाए, जन्म मरण मिट जाय। सुख रुपयों से कैसे होगा ? रुपए से भौतिक सुख हो जाएगा (खर्च करे तो)। वास्तविक उपकार को समझ जावे तो जन्म मरण क्यों हो ? महत्व जड़ता का है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली का क्या महत्व है ? आज लोग कहते हैं - अर्थार्थी भक्त है। तो वह झूठ, कपट, बेईमानी, कालाबाजारी देवता के भक्त हैं। इनका आश्रय लिया है। और धन कमाते हैं वो आदमी बड़े माने जाते हैं। भगवान में लगना चाहिए। कुएं में भांग पड़ी है। क्या साधु ! क्या गृहस्थ ! सबका लक्ष्य रुपया ही बन गया। तो सुख, कल्याण समझ में कैसे आए!

एक तरफ धन है, एक तरफ धन का खर्चा है, मिलान करो। धन जब काम आवेगा, खर्च से ही काम आएगा। आपके भी तभी काम आवेगा, दूसरों के भी तभी काम आएगा। धन का संग्रह अभिमान पैदा करता है। त्याग से शांति मिलती है। धन से आसुरी संपत्ति बढ़ी कि दैवी संपत्ति बढ़ी। ज्यादा धन वाले के ऊपर राज्य की, चोर की, साधु की, ब्राह्मण की, बेटे - बेटी सब की दृष्टि रहती है। धनी पर सबकी निगाह रहती है। धनवान के यहां काम करने वाले कहते हैं - कि सेठ के पास धन तो हो गया, पर अक्ल नहीं है। देखो सार बात बातावें रुपयों का सदुपयोग बढ़िया है, ऐसे समय का सदुपयोग बढ़िया है। हरेक चीज का सदुपयोग हो। मनुष्य शरीर की महिमा बताई है, उससे नरक में भी जा सकता है और स्वर्ग में भी जा सकता है। तो क्या नरक की महिमा है। महिमा मनुष्य शरीर (विवेक की) है। जिससे अपना कल्याण कर ले। उपकार भी सदुपयोग से ही होगा।

दिल्ली में सरकार बनाते ही बीजेपी ने पुरानी गाड़ियों को हटाने का ले लिया था फैसला : सौरभ भारद्वाज

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाने को लेकर कोर्ट के आदेश का बहाना बना रही बीजेपी की पोल खुल गई है। ''आप'' के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार बनते ही बीजेपी ने पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ले लिया था। फरवरी में बीजेपी सरकार ने शपथ ली और चंद दिन बाद 01 जुलाई को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एलान किया कि 31 मार्च के बाद पुरानी गाड़ियों को तेल नहीं मिलेगा। हालांकि इसे लागू एक जुलाई से किया गया। आज बीजेपी जिस सीएक्यूएम के आदेश का सहारा ले रही है, वह आदेश तो मंत्री के एलान के काफी दिनों बाद 27 अप्रैल को आया था। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी ने पहले ही ऑटोमोबाइल कंपनियों से सांठगांठ कर ली थी और उनको करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए यह तुगलकी फरमान जारी किया, ताकि दिल्ली के 61 लाख लोग नई गाड़ी खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं।

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्लीवालों को बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने अपनी एकजुटता के जरिए बीजेपी सरकार के कई तुगलकी फरमानों को वापस लेने के लिए मजबूर किया है। जब पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने पर रोक लगाने की बात कही जा रही थी, तब बीजेपी सरकार के मंत्री उछल-उछल कर कह रहे थे कि किसी पुराने वाहन को छोड़ा नहीं जाएगा। पेट्रोल पंपों पर पुरानी गाड़ियों को जब्त करने के लिए 400 टीमें लगाई जाएंगीं और बीजेपी पूरी तरह चुप थी। दिल्ली सरकार के इस तुगलकी फरमान का सिर्फ दिल्ली की आम जनता और आम आदमी पार्टी विरोध कर रही थी। ''आप'' ने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लगातार इस आदेश का विरोध किया गया।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब बीजेपी की चोरी पकड़ी गई तो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएक्यूएम को चिट्ठी लिखी कि सरकार पुरानी गाड़ियों डीजल-पेट्रोल नहीं देने का प्रतिबंध नहीं लगा पाएगी। इसके बाद बीजेपी सरकार अपने ही बुने जाल में फंस गई। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएक्यूएम को लिखे पत्र में कहा है कि 23 अप्रैल 2025 को सीएक्यूएम की तरफ से दिल्ली सरकार को निर्देश आया कि पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजन देना बंद कर दिया जाए। लेकिन सीएक्यूएम से पत्र मिलने से एक माह पहले ही 01 मार्च 2025 को मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुद प्रेसवार्ता कर एलान किया था कि सरकार 31 मार्च से पुरानी गाड़ियों को डीजल-पेट्रोल देना बंद कर देगी।

उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि बीजेपी ने सरकार बनने के तुरंत बाद ही तय कर लिया था कि दिल्ली की सड़कों से 61 लाख पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाकर लोगों को नई गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर करना है। सीएक्यूएम केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। बीजेपी की दिल्ली सरकार द्वारा 23 अप्रैल 2025 को सीएक्यूएम से मिलीभगत कर पुरानी गाड़ियों को डीजल-पेट्रोल नहीं देने को लेकर पत्र लिया गया और सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। सीधे तौर पर बीजेपी की केंद्र सरकार का सीएक्यूएम और दिल्ली सरकार की मिलीभगत से दिल्ली के लोगों पर यह तुगलकी फरमान थोपा गया। इनकी तरफ से कोशिश की गई कि नई लाखों गाड़ियों की बिक्री कराई जाए।

सौरभ भारद्वाज ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा 1 मार्च को दिया गया बयान सुनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने यह प्रतिबंध किसी मजबूरी में नहीं लगाया था। बल्कि सरकार के मंत्री ईंधन न देने को लेकर पीठ थपथपा रहे थे। धक्काशाही चल रही थी। मंत्री ने बयान में कहीं नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी का आदेश आ गया है, सरकार को मजबूरी में पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटानी होगी। तैयारी पूरी नहीं होने की वजह से बीजेपी सरकार 31 मार्च से ईंधन देने पर प्रतिबंध नहीं लगा पाई। फिर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया। बीजेपी एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश की बात कर रही है, वह तो 2015 में आया था। इसके बाद कोई नया आदेश नहीं आया है। सीएक्यूएम के आदेश की जांच होनी चाहिए, इसमें बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा है। इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे इसकी जांच की जाए। यह स्कीम कहां और क्यों बनाई गईं कि इस तरह का प्रतिबंध दिल्ली वालों पर थोपा गया। 03 जुलाई को मनजिंदर सिंह सिरसा का सीएक्यूएम को लिखा गया पत्र मात्र लीपापोती है।

''आप'' पार्षदों ने हाउस में यह मुद्दा उठाया, तो मेयर ने स्टैंडिंग कमेटी में कार्य योजना लाने की बात कही, लेकिन नहीं लाए- अंकुश नारंग

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के सेंट्रल जोन में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने सेंट्रल जोन के पार्षद मंडल के साथ शुक्रवार को एमसीडी के कमिश्नर से मुलाकात की और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। अंकुश नारंग ने बताया कि हमने कमिश्नर से सेंट्रल जोन में हर गली-हर सड़क पर फैले गंदगी के अंबार को जल्द से जल्द साफ कराने की मांग की है। दिल्ली में मनसून ने दस्तक दे दी है। चारों तरफ कूड़ा फैला होने से मौसमी बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इस बाबत 04 जून को मैंने मेयर को भी चिट्ठी लिखी थी। मेयर ने दो दिन में सफाई कराने का आश्वास दिया था, लेकिन सफाई नहीं कराई। फिर उन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाया। उस दौरान मेयर ने कहा कि यह स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में भी कोई कार्ययोजना नहीं लाई गई।

इस दौरान एमसीडी नेता विपक्ष अंकुश नारंग और निगम पार्षद मंडल में सेंट्रल जोन से वार्ड-142 सारिका चौधरी, वार्ड-184 हेमा श्रीचंद वोहरा, वार्ड- 168 पंकज गुप्ता, वार्ड- 179 राकेश लोहिया, वार्ड-170 भागवीर चौधरी उपस्थित रहे।

अंकुश नारंग ने पत्र में कहा है कि दिल्ली के सेंट्रल जोन में सफाई व्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए है जिससे स्थानीय निवासियों का जीना दूभर हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सेंट्रल जोन में कोई कंशेसनेयर/एजेन्सी निगम द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्र करने के लिए चयनित नहीं की गई। वर्तमान में सेंट्रल जोन में 25 पार्षद हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के सात पार्षद हैं। सभी 25 पार्षदों एक का कहना है कि उनके क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और जगह-जगह गन्दगी के ढेर लगे हुए है। लेकिन ''आप'' पार्षदों ने सिर्फ इसकी आवाज उठाई है। बीजेपी एमसीडी की सत्ता में हैं। इसके बाद भी बीजेपी पार्षद भी इस कूड़े की दिक्कत से झुलस रहे हैं, लेकिन फिर भी वह शांत है। बीजेपी ने उनको शांत करा रखा है। सेंट्रल जोन के हालात बहुत बुरे हैं।

अंकुश नारंग ने कहा है कि पिछले जून में आयोजित निगम के सदन में सेंट्रल जोन में सफाई व्यवस्था की स्थिति हमने उठाई थी और सेंट्रल जोन में कंशेसनेयर की नियुक्ति की मांग की थी। उस हाउस में यह बताया गया था कि कंशेसनेयर की नियुक्ति के लिए आइटम निगम की आगामी स्थायी समिति की सभा में लाया जाएगा। लेकिन बेहद खेद का विषय है कि 27 जून 2025 को स्थायी समिति की सभा हुई, लेकिन उसमें सेंट्रल जोन की सफाई व्यवस्था को दूरूस्त करने के लिए न तो कोई कार्य योजना लाई गई और न ही कंशेसनेयर लगाने की कोई आइटम लाई गई। उन्होंने कहा कि नालों की सफाई के बाद गाद को सड़क के किनारे छोड़ दिया गया है। यह मिट्टी अब पुनः नाले में जा रही है, जिससे जल भराव हो रहा है। इसलिए सड़क पर पड़ी नालों की गाद उठाने के लिए हर पार्षद को एक टाटा 407 दी जाए ताकि जल भराव न हो सके। पार्षदों के पास टाटा 407 की सुविधा नहीं है। जहां पर 10 टिंपर थे, वहां दो रह गए हैं, जहां 15 थे, वहां तीन टिंपर रह गए हैं। जिसकी वजह से सड़कों पर कूड़ा फैला हुआ है।

अंकुश नारंग ने कहा कि सेंट्रल जोन में सफाई व्यवस्था की दयनीय स्थिति के लिए वहां के स्थानीय निवासियों में अत्यंत रोष है ओर क्षेत्रीय निगम पार्षदों को उनका सामना करने में काफी कठिनाई हो रही है। जैसा कि आपको विदित है कि इस समय मानसून दिल्ली में दस्तक दे चुका है और समय-असमय कहीं भी बारिश होने लगती है जिसके फल स्वरूप सेंट्रल जोन में गन्दगी के कारण जगह-जगह जल भराव की शिकायतें मिल रही है और सेंट्रल जोन में जल-जनित बिमारियां फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों ने हिमाचल यात्रा के दौरान मनाया संगीत संध्या और जन्मदिन समारोह

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। सिल्वर लाइन सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन द्वारा हिमाचल प्रदेश की मनोरम वादियों की यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को तनाव व अवसाद से दूर रखते हुए समाज से जुड़ाव बढ़ाना और हिमाचल के नागरिकों से नेटवर्क स्थापित करना था।

इस यात्रा के दौरान राजगढ़ में एक भव्य संगीत संध्या और सदस्य के जन्मदिन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरी यात्रा के दौरान भजन, पुराने और नए फिल्मी गीतों की धुनों पर सभी ने संगीत और नृत्य का आनंद लिया।

संगीत संध्या में एस.पी. मल्होत्रा ने भावुकता से ₹हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोता भी रहा, हँसता भी रहा...₹ गाया। राकेश जेठी ने ₹पुकारता हूँ मैं गली-गली...₹ और ₹मुसाफ़िर हूँ यारों, न घर है न ठिकाना...₹ से समा बांध दिया।

उषा जैन ने ₹कुर्ती मेरी छिंट दी, दुपट्टा मेरा लहरिया...₹ और ₹नहर वाला पुल ता ब्लैक हो गया...₹ जैसे गीतों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रेखा गोयल ने ₹दिल कह रहा है रुक जा, यहीं रुक जा...₹ और सुरिंदर वर्मा ने ₹आ चल के तुझे मैं ले चलूं...₹ प्रस्तुत कर माहौल को रूमानी बना दिया।

सदस्य सुरिंदर वर्मा ने बताया कि इस यात्रा ने सभी प्रतिभागियों को न केवल मानसिक ताजगी दी, बल्कि उन्हें एक-दूसरे के करीब लाकर एक सशक्त समुदाय की अनुभूति भी कराई। राजगढ़ से आगे बढ़ते हुए दल ने हरबीन वैली का भ्रमण किया, जहाँ सदस्यों ने हरे-भरे वातावरण और ताजगी भरे मौसम का आनंद उठाया। इस प्रेरणादायक यात्रा का नेतृत्व एसोसिएशन के महासचिव अशोक बंसल ने किया, जो अध्यक्ष टी.के. गोयल के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।

करोल बाग के 'विशाल मेगा मार्ट' में लगी आग, एक व्यक्ति के लापता होने की आशंका

परिवहन विशेष न्यूज

नयी दिल्ली। मध्य दिल्ली के करोल बाग इलाके में शुक्रवार को एक शॉपिंग परिसर में आग लग गई और पुलिस को एक व्यक्ति के लापता होने की आशंका है।

पुलिस ने एक बयान में कहा कि पदम सिंह रोड स्थित चार मंजिला 'विशाल मेगा मार्ट' इमारत की दूसरी मंजिल पर शाम 6.44 बजे आग लगने की सूचना मिली।

बयान के अनुसार, दमकल की कुल 13 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि, पुलिस ने एक व्यक्ति के लापता होने की आशंका जताई है।

बयान में कहा गया है, ''यह विशाल मेगा मार्ट का परिसर है, जहां किराने का सामान और कपड़े बेचे जाते हैं। आग मुख्य रूप से चार मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल तक ही सीमित रही।'

पुलिस, अग्निशमन और आपदा प्रतिक्रिया दल संयुक्त रूप से खोज और बचाव अभियान चला रहे हैं। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।

फन वे लर्निंग एनजीओ के बच्चों को, जिन्होंने अपने कोर्स पूरे किए, परीक्षा के बाद सर्टिफिकेट दिए गए।

आरएसएस ने दिखाए अपने नुकीले दांत : (आलेख : एम. ए. बेबी, अनुवादक : संजय पराते)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को हटाने की आरएसएस नेतृत्व द्वारा हाल ही में की गई मांग न केवल शब्दार्थ पर हमला है, बल्कि भारतीय गणतंत्र के आधारभूत दृष्टिकोण पर सीधा हमला है। हमारा संविधान भारत के गौरवशाली उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह उन विभिन्न आंदोलनों द्वारा समर्थित मूल्यों को आत्मसात करता है, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए हाथ मिलाया था। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इसके सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से हैं। ये ऐसे मूल्य हैं, जो केवल प्रस्तावना तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि संविधान में हर जगह दिखाई देते हैं और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों आदि में परिलक्षित होते हैं।

आरएसएस महासचिव का यह आह्वान 50 साल पहले घोषित आपातकाल की आलोचना की आड़ में किया गया है, क्योंकि 1976 में आपातकाल के दौरान लागू किए गए 42वें संशोधन के ज़रिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द शामिल किए गए थे। इन सिद्धांतों को बदनाम करने के लिए आपातकाल की आड़ लेना आरएसएस का एक कपटपूर्ण कदम है, खासकर तब, जब उन्होंने खुद उस समय अपने अस्तित्व के लिए इंदिरा गांधी सरकार के साथ सांठगांठ की थी। संविधान को कमज़ोर करने के लिए अब उस काल का उपयोग करना सरासर पाखंड और राजनैतिक अवसरवाद को दर्शाता है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता उन बुनियादी विचारों में से हैं, जो भारत को एक आधुनिक लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं।

सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता

भारतीय संविधान में समाजवाद का उल्लेख सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने, असमानता के उन्मूलन और कल्याणकारी राज्य के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक मजबूत धारा का प्रतिबिंब है, जिसने न केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि सभी प्रकार के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। कम्युनिस्टों के अलावा, भगत सिंह और उनके साथी स्वतंत्रता संग्राम में इस प्रवृत्ति के सबसे अच्छे उदाहरण हैं।

भारतीय संविधान में निश्चित रूप से समाजवादी समाज बनाने का सपना नहीं है -- जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व हो और सभी प्रकार के आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न का उन्मूलन हो -- जैसा कि सीपीआई (एम) की आकांक्षा है। सीपीआई (एम) एक स्वतंत्र और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार वाले समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जो अभी तक हासिल नहीं हुआ है। बहरहाल, एक ऐसे समाज में, जिसमें बहुसंख्यक लोग स्वतंत्रता से च्युत और असमान थे, स्वतंत्रता बढ़ाने और असमानताओं को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।

42वें संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय" का वादा किया गया था और "स्थिति और अवसर की समानता" की चाहत रखी गई थी। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि हालांकि 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से "समाजवादी" शब्द जोड़ा, लेकिन हमारे संविधान के प्रावधानों में 'समाजवाद की भावना' हमेशा मौजूद थी।

भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए मौलिक अधिकार उस दिशा में प्रमुख कदम थे। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांतों के साथ पढ़े गए ये अधिकार शोषण से मुक्त समाज की दृष्टि को सुनिश्चित करते हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को बरकरार रखा जाता है।

भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत -- भाग IV, अनुच्छेद 36-51 -- में समाजवादी _दृष्टिकोण की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि "राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यथासंभव प्रभावी ढंग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास करेगा, जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को संसूचित करेगा।"

अनुच्छेद 39 में आगे कहा गया है कि "राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को इस तरह से निर्देशित करेगा -- (अ) कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं, का समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों पर अधिकार हो ; (ब) कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से वितरित किया जाए कि यह सर्वसामान्य भलाई के लिए सर्वोत्तम प्रयास हो; (स) कि आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन और उत्पादन के साधनों का सामान्य हानि के लिए केन्द्रीकरण न हो; (द) कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो... ।"

ये अनुच्छेद भारतीय संविधान में समाहित समाजवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 41 में रोजगार प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार के बारे में ; अनुच्छेद 42 में काम के न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान के बारे में और अनुच्छेद 43 में जीवन निर्वाह मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये प्रावधान सिर्फ़ आकांक्षापूर्ण नहीं हैं -- इन्होंने भारत में भूमि सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना से लेकर सामाजिक कल्याण योजनाओं की स्थापना तक ऐतिहासिक कानून और न्यायिक व्याख्या को निर्देशित किया है।

हालांकि निर्देशक सिद्धांत केवल सरकार को निर्देश हैं और कानूनी रूप से लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन संविधान सभा में हुई गहन बहस के नतीजे के रूप में वह यहां मौजूद है। उन्हें कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाने की मांग को खारिज करना राज्य के वर्ग चरित्र को दर्शाता है। शासक वर्ग समाजवाद के विचार को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकता था, क्योंकि जनता का एक बड़ा तबका इन विचारों का समर्थन करता था।

एक बुनियादी सिद्धांत

भारतीय संविधान में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता केवल धार्मिक तटस्थता के अभिप्राय में नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक आश्वासन है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी नागरिक को उसकी आस्था के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। प्रस्तावना के मूल पाठ में, 1976 में "धर्मनिरपेक्ष" शब्द को जोड़ने से पहले ही, "विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता" और "व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता ..." का वादा किया गया था।

भाग III - मौलिक अधिकार - अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं और यह भारतीय गणराज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को फिर से रेखांकित करता है। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य करने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 28 पूरी तरह से राज्य के कोष से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित कर सकें। यह राज्य द्वारा संचालित या राज्य के कोष से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में केवल धर्म आदि के आधार पर प्रवेश से इंकार करने पर रोक लगाता है और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने की अनुमति देता है।

ये अनुच्छेद यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य न तो किसी धर्म को पहचानेगा और न ही उसे विशेषाधिकार देगा और हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, समान अधिकार और सुरक्षा का आनंद लेगा। इसके अलावा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कमजोर तबकों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा का निर्देश दिया गया है, जैसा कि अनुच्छेद 46 में निर्दिष्ट किया गया है। कई आधिकारिक अध्ययनों -- जिसमें सच्चर समिति और रंगनाथी मिश्रा आयोग शामिल हैं -- ने साबित किया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विभिन्न वर्ग वास्तव में समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में कमज़ोर हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात की बार-बार पुष्टि की है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के 'मूल ढांचे' का हिस्सा है। न्यायालय ने माना है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है -- राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार और किसी भी राज्य-धर्म का अभाव।

यह ध्यान देने योग्य है कि मूल संरचना सिद्धांत को 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में पेश किया गया था। यह सिद्धांत मानता है कि भारतीय संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल या बुनियादी ढांचे को बदल या नष्ट नहीं कर सकती, यानी संविधान का मूल ढांचा अपरिवर्तनीय है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 42वां संशोधन जिसने संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को समाहित किया, इस ऐतिहासिक फैसले के तीन साल बाद 1976 में लागू किया गया था। फिर भी, ये संशोधन किए जा सकते थे -- खासकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले की पृष्ठभूमि में -- क्योंकि, ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते थे।

भारत के विचार से अविभाज्य

यह दावा करना एक भ्रांति है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता 1970 के दशक से केवल 'जोड़े गए' या 'थोपे गए' हैं। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा की बहसें और भारत के गौरवशाली उपनिवेशवाद-विरोधी स्वतंत्रता संग्राम का जीवंत अनुभव सभी इस बात की गवाही देते हैं कि ये मूल्य गणतंत्र के संस्थापकों की दृष्टि के केंद्र में थे। सामाजिक और आर्थिक न्याय, समानता और बंधुत्व के प्रति भारतीय संविधान की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से समाजवादी है। धार्मिक स्वतंत्रता, गैर-भेदभाव और अल्पसंख्यक अधिकारों की इसकी गारंटी स्वाभाविक रूप से धर्मनिरपेक्ष है। भले ही प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिए जाएं, लेकिन संविधान का मूल दर्शन, संरचना और प्रावधान अपने सार में अपरिवर्तित रहेंगे।

संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अंबेडकर का 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में दिया गया अंतिम भाषण गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो इस तर्क को मजबूत करता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार - जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की नींव बनाते हैं - भारतीय संविधान की भावना और संरचना में अंतर्निहित हैं। उन्होंने कहा, "हमें सिर्फ़ राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता, जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसी जीवन शैली, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है... स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। न ही स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से अलग किया जा सकता है। समानता के बिन स्वतंत्रता, कुछ लोगों की बहुतों पर सर्वोच्चता पैदा करेगी। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता, कुछ लोगों की बहुतों पर सर्वोच्चता पैदा करेगी। बंधुत्व के बिना, स्वतंत्रता और समानता चीजों का स्वाभाविक क्रम नहीं बन सकती।"

उन्होंने आगे कहा, "सामाजिक स्तर पर, भारत में हमारे पास एक ऐसा समाज है, जो क्रमिक असमानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कुछ लोगों के लिए उत्थान और दूसरों के लिए पतन। आर्थिक स्तर पर, हमारे पास एक ऐसा समाज है, जिसमें कुछ लोगों के पास अपार संपत्ति है, जबकि कई लोग घोर गरीबी में रहते हैं। 26 जनवरी 1950 को, हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में, हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण, एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। हम कब तक विरोधाभासों का यह जीवन जीते रहेंगे? हम कब तक अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? अगर हम इसे लंबे समय तक नकारते रहेंगे, तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही ऐसा करेंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द दूर करना होगा, अन्यथा असमानता से पीड़ित लोग राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को नष्ट कर देंगे, जिसे इस सभा ने अभी तक कड़ी मेहनत से बनाया है।" अंबेडकर का भाषण इस बात की जोरदार पुष्टि करता है कि भारतीय संविधान सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था -- ये सिद्धांत ही समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का सार हैं। उनके शब्द इन आधारभूत मूल्यों को कमजोर करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह हैं।

आरएसएस का पर्दाफाश

आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले की भारतीय संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाने की मांग महज ऐतिहासिक सटीकता के लिए एक मासूम आह्वान नहीं है, बल्कि भारतीय गणतंत्र की नींव को कमजोर करने की एक सोची-समझी चाल है। उनका तर्क कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द डॉ. अंबेडकर के मूल मसौदे का हिस्सा नहीं थे, इस तथ्य की अनदेखी करता है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत पूरे संविधान में परिलक्षित होते हैं, और 42वें संशोधन ने केवल वही स्पष्ट किया है, जो हमेशा इसके पाठ और भावना में निहित था। वास्तव में, धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन से पहले भी अनुच्छेद 25(2)(ए) में मौजूद है। अनुच्छेद 38 का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, जो राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का निर्देश देता है, जो समाजवाद की ओर झुकाव को दर्शाता है।

आरएसएस ने हमेशा असमानता और पितृसत्ता को मजबूत करने और भारत की राष्ट्रीय पहचान को धर्मतंत्र के आधार पर फिर से परिभाषित करने की कोशिश की है। प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को मिटाने का उनका प्रयास वास्तव में इतिहास को फिर से लिखने, हमारे उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को अमान्य करने और एक धर्मतंत्रीय, बहुसंख्यकवादी राज्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास है। यह भारत के बहुलतावादी और लोकतांत्रिक समाज के विचार के लिए एक खतरा है।

भारतीय संविधान सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिन पर भारतीय गणतंत्र की इमारत खड़ी है।

उन मूल्यों पर हमला करके, आरएसएस की असली मंशा उजागर हो गई है -- यह हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित और गारंटीकृत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य को नष्ट करने से कम नहीं है। यह मांग भारतीय संविधान को मनुस्मृति से बदलने, भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को नष्ट करने और हिंदू राष्ट्र बनाने के आरएसएस के लंबे समय से चले आ रहे एजेंडे को उजागर करती है। वे सभी लोग, जो स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को संजोते हैं -- जो ऐसा संघर्ष था, जिसका आरएसएस हिस्सा नहीं था और यहां तक कि उसने भारत के युवाओं से इसका हिस्सा बनकर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करने का आह्वान भी किया था -- उन्हें संविधान की रक्षा में एकजुट होना चाहिए और भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध करना चाहिए।

(लेखक माकपा के महासचिव हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।)

मृदुल वृन्दावन धाम में भव्य कलश यात्रा के साथ धूमधाम से प्रारंभ हुई श्रीमद्भागवत कथा

विश्वविख्यात भागवताचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने समस्त भक्तोंश्रद्धालुओं को श्रवण कराई महात्म्य की कथा

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। छटीकरा रोड़ स्थित मृदुल वृन्दावन धाम में द भागवत मिशन फाउंडेशन एवं भागवत परिवार समिति (रजि.) दिलशाद गार्डन,दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में अष्टदिवसीय श्रीमद्भागवत कथा एवं श्रीगुरू पूर्णिमा महोत्सव अत्यन्त श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ प्रारंभ हो गया है ।महोत्सव का शुभारभ श्रीहरिदासी वैष्णव संप्रदायाचार्य विश्वविख्यात भागवताचार्य आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण महाराज, श्रीनाभापीठाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुरु स्वामी सुतीक्ष्णदास देवाचार्य महाराज एवं आचार्य कुटी श्रीकृष्ण मंदिरम-के संस्थापक जगद्गुरु स्वामी रामप्रपन्नाचार्य महाराज ने ठाकुर श्रीबांकेबिहारी महाराज के चित्रपट के समक्ष वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य दीप प्रज्ज्वलित करके किया ।इससे पूर्व श्रीमद्भागवतजी की भव्य कलश यात्रा निकाली गई ।जिसमें पीत वस्त्र पहने सैकड़ों महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण किए साथ चल रही थीं ।साथ ही असंख्य भक्त- श्रद्धालु श्रीहरिनाम संकीर्तन करते हुए शामिल हुए ।तत्पश्चात व्यासपीठ पर आसीन विश्वविख्यात भागवताचार्य आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण महाराज ने देश-विदेश से आए समस्त भक्तश्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत के महात्म्य की कथा श्रवण कराई।

श्रद्धेय गोस्वामी मृदुल कृष्ण महाराज ने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया है। भगवान विष्णु की समस्त लीलाओं और अवतारों की कथाओं का ज्ञान कराने वाला यह ग्रंथ सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, द्वैत-अद्वैत, निर्गुण-सगुण का ज्ञान प्रदान करता है। वस्तुतः श्रीमद्भागवत महापुराण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अक्षय भंडार है। इसीलिए इस ग्रंथ के श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय हो जाता है और भगवान की भक्ति सहज में ही प्राप्त होती है।

व्यासपीठाधीन आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण महाराज ने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से बुद्धि शुद्ध होती है, संशय दूर होता है, और हमारे मन को शांति मिलती है। यह कथा आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके ईश्वर के चरणों में स्थापित करती है ।इसीलिए इसे मोक्ष का साधन भी कहा जाता है। यह कथा अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक परब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण के जीवन, लीलाओं और भक्ति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं,साथ ही श्रोताओं को आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करती हैं।

महोत्सव में मुख्य यजमान श्रीमती हिना-विकास अग्रवाल, श्रीमती श्याम लता-कुसुम पाल शर्मा, श्रीमती अरुणा शर्मा, प्रख्यात साहित्यकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, आचार्य किशोर कुमार शर्मा, डॉ. राधाकांत शर्मा, आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन

बंदायु। गुरुवार को बदायूं के कृष्णा लॉन में #स्नेह_मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें बदायूं के पूर्व विभाग प्रचारक श्रीमान विशाल जी, पूर्व जिला प्रचारक श्रीमान घनश्याम जी एवं नव आगंतुक विभाग प्रचारक श्रीमान सुधांशु जी, जिला प्रचारक भरत लाल जी, नगर प्रचारक तुलसी जी रहना हुआ ।इस अवसर पर नगर के सभी गणमान्य बंधु एवं बहिनें उपस्थित रहे साथ ही उन्होंने अपने कुछ संस्मरण भी व्यक्त किए। माननीय विभाग संघ चालक श्रीमान सुनील जी जी एवं विभाग कार्यवाह श्रीमान जगजीवन राम जी ने अपने विचार व्यक्त किए ।कार्यक्रम के समापन में क्षेत्रीय कार्यकारणी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान मनीराम जीका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस अवसर पर जिला कार्यवाह #मून जी सह जिला शारीरिक प्रमुख अनुज जी सह नगर कार्यवाह #अभिनव जी शारीरिक प्रमुख कुशाल जी एवं वेदरतन जी, मुनेंद्र जी आदि स्वयंसेवक उपस्थित रहे

जन्म और मृत्यु के भय को समाप्त करने वाला दिव्य ग्रंथ है श्रीमद्भागवत महापुराण : पण्डित रामांश पाराशर

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। श्रीहित हरिवंश नगर स्थित वानप्रस्थ धाम फेस-1 में श्रीराधा माधव सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में अष्टदिवसीय गुरुपूर्णिमा महोत्सव अत्यन्त श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ प्रारम्भ हो गया है ।महोत्सव का शुभारभ वानप्रस्थ धाम के संस्थापक डॉ. चतुर नारायण पाराशर महाराज के पावन सानिध्य में ठाकुरजी के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया ।इससे पूर्व गाजे-बाजे के मध्य श्रीमद्भागवतजी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई ।जिसमें पीत वस्त्र पहने हुए सैकड़ों महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण किए साथ चल रही थीं ।तत्पश्चात मुख्य यजमान श्रीमती किरण शुक्ला व डॉ. अमरेश चंद्र शुक्ला द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य व्यासपीठ का पूजन-अर्चन किया गया।

व्यास पीठ पर आसीन पण्डित रामांश पाराशर महाराज ने देश-विदेश से आए समस्त भक्तों-श्रद्धालुओं को अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा श्रीमद्भागवत का महात्म्य श्रवण कराते हुए कहा कि महर्षि वेदव्यासजी महाराज के द्वारा रचित और श्रीशुकदेवजी के मुख से प्रवाहित श्रीमद्भागवत महापुराण सम्पूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष बताने वाला तथा जन्म और मृत्यु के भय को समाप्त करने वाला दिव्य ग्रंथ है ।ये हमारे अंदर भक्ति प्रवाह को बढ़ाकर भगवान श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे मुख्य साधन है। प्रेम से इसका श्रवण करने से हमारा मन और तन दोनों ही पवित्र हो जाते हैं।

महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे विश्वविख्यात भागवताचार्य डॉ.श्याम सुंदर पाराशर, महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज, आचार्य नेत्रपाल शास्त्री (गुरुजी), प्रख्यात साहित्यकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, डॉ. शिवम साधक महाराज एवं पूर्व प्राचार्य डॉ. रामसुदर्शन मिश्र आदि ने वानप्रस्थ धाम के संस्थापक डॉ. चतुर नारायण पाराशर महाराज के यशस्वी सुपुत्र पण्डित रामांश पाराशर के प्रथम बार श्रीमद्भागवत की कथा कहने पर उन्हें अनन्त शुभकामनाएं व बधाई दीं ।साथ ही प्रभु से यह कामना की, कि वे भी अपने पूज्य पिता श्री की भांति विश्वभर में भारतीय वैदिक सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार कर असंख्य व्यक्तियों को धर्म व प्रभु भक्ति के मार्ग से जोड़े।

महोत्सव में आए सभी आगंतुक अतिथियों को डॉ. चतुर नारायण पाराशर ने स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र एवं ठाकुरजी का पटुका-प्रसादी-माला आदि भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर सुशील राजवंशी (बीकानेर), आचार्य पवन पाराशर, डॉ. राधाकांत शर्मा, पंकज गुप्ता आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

रमजानपुर प्रीमीयम लीग का भव्य उद्घाटन

परिवहन विशेष न्यूज

बदायूं के ग्राम रमजानपुर में आज रमजानपुर प्रीमियर लीग 2025 क्रिकेट मैच का भव्य उद्घाटन डा० अच्छन मियाँ (भदसिया)एवं डा0 हाशमीन अरसलान पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमजानपुर बदायूं द्वारा किया गया जिसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ पत्रकार हामिद अली खान राजपूत इंतजार हुसैन हसीव खान वासिल हुसैन शाकिर खान जाकिर खान इशरत मिलन रियाजउल हुसैन शादाब हुसैन रिफ़ाकात हुसैन मुजद्दन अली रियाज़ुद्दीन सच्चन शफात वगैरहा ने मुख्य रूप से शिरकत की यह टूर्नामेंट आज 3 जुलाई से शुरू होकर 13 जुलाई तक चलेगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की टीमें प्रतिभाग करेंगी।

वाराणसी बजरडीहां क्षेत्र में शनिवार को रात 9 बजें इकबाल अहमद खलिफा के नेतृत्व में अखाड़ा निकाला जाएगा

जिला वाराणसी संवाददाता वसीम अहमद

वाराणसी बजरडीहां क्षेत्र में मोहर्रम की नौ तारीख को हमीद नगर कुडीग़ा से इकबाल अहमद खलिफा के अध्यक्षता में अखाड़ा निकाला जाएगा जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों को खेला जाएगा जैसे पटा बना लकड़ी ढ़ाल सटका बनैठी भाला इत्यादि प्रकार के खेलों को खेला जाएगा शनिवार रात 9 बजें से सुबह चार बजे तक बजरडीहॉ के सभी इमामबाड़ा में जाकर सलामी दिया जाएगा।

भारतीय फ़न ए सिपहगिरी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य इकबाल अहमद खलिफा ने बताया कि मोहर्रम की नौ को रात 9 बजें से सुबह 4 बजे तक पुरे बजरडीहॉ क्षेत्र में अखाड़े को खेला जाता है। उसके बाद मोहर्रम की बारह तारीख को दोपहर 2 बजें से हमीद नगर कुडीग़ा से अखाड़े का जुलूस निकाला जाता है जो बजरडीहॉ इकबाल अहमद खलिफा के नेतृत्व में अखाड़े के जुलूस निकाला जाता है जो तेलियाना चौराहा बजरडीहॉ पुलिस चौकी धारारा आटों स्टैंड छाई सुदामापर कंकड़हाबिर कमच्छा थाना भेलूपुर ज्योतिया पार्क रेवड़ी तलाब गोदौलिया नई सड़क शेख़ सलीम फाटक होते हुए लल्लापुरा फातमान जाकर सलामी देकर समाप्त होता हैं।

भारतीय फ़न ए सिपहगिरी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पूर्व मिडिया प्रभारी वसीम अहमद

सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है सहकारिता क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक राजनीतिक संगम हो तो सटीक सफ़लता की गारंटी

वैश्विक स्तरपर सहकारी समितियों के लिए उद्यमशीलता पारिस्थितिकीतंत्र और प्रतिष्ठानों को मज़बूत करना, सहयोगपूर्ण कानून, नीतिगत कार्य मील का पत्थर साबित होगा- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावननीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर सर्वविदित है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम अकेले करते हैं तो उनकी क्षमता सीमित होती है परंतु यदि वही एक से अधिक व्यक्तियों के सामूहिक कार्यों से किया जाए तो उनकी ताकत, बल, संसाधन,ज्ञान तेजी से कई गुना अधिक हो जाता हैजिसमें आने वाली हर चुनौतियों का मुकाबला कर सफलता पांने की सटीक कुंजी है, यानें हम आपसी सहयोग कर एक संगठन बनाकर, जिसे सहकारी समिति कहा जाता है, कोई भी काम मजबूती से कर सकते हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि सहकारी समितियां ₹एक और एक ग्यारह₹ की तरह काम करती हैं क्योंकि वे सदस्यों के सामूहिक प्रयासों और सहयोग के माध्यम से अधिक ताकत और सफलता प्राप्त करती हैं। व्यक्तिगत रूप से, सदस्यों की क्षमताएं सीमित हो सकती हैं, लेकिन जब वे एक साथ आते हैं और एक सहकारी समिति के रूप में काम करते हैं, तो वे अधिक संसाधन, ज्ञान और शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे वे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अधिक हासिल कर सकते हैं ।संसाधनों का एकीकरण, जोखिम साझा करना,ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान,बार्गेनिंग पावर, सामुदायिक विकास क़ा लक्ष्य होता है, क्योंकि सब मिलकर कर रहे हैं, इसीलिए ही हम 5 जुलाई 2025 शनिवार को हम अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहे हैं। चूँकि वैश्विक स्तरपर सहकारी उद्यनशीलता पारिस्थितिकी तंत्र प्रतिष्ठा को मजबूत करना, सहयोगपूर्ण कानून व नीतिगत कार्य मील क़ा पत्थर साबित होगा, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, सहकारिता क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संगम से सटीक सफ़लता की गारंटी हैँ, सहकारिता एक बेहतर दुनियाँ के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान है।

साथियों बात अगर हम 5 जुलाई 2025 शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस मनानेकी करें तो सहकारिता: बेहतर विश्व के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान को आगे बढ़ाना इस वर्ष का आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान हो रहा है - एक दुर्लभ, दशक में एक बार आने वाला अवसर, जो अधिक न्यायपूर्ण, अधिक लचीले समाजों के निर्माण में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के दौर में, इस वर्ष की थीम बहुत कुछ कहती है। सहकारी समितियाँ - अपने सदस्यों के स्वामित्व वाली और उनके द्वारा संचालित व्यवसाय - यह दिखा रही हैं कि लाभ से पहले लोगों, ग्रह और उद्देश्य को प्राथमिकता देकर मजबूत समुदायों का निर्माण कैसे संभव है। स्वास्थ्य और आवास से लेकर कृषि, वित्त और स्वच्छ ऊर्जा तक, सहकारी समितियाँ वास्तविक दुनिया के समाधान प्रदान कर रही हैं जो समावेशी, लोकतांत्रिक और टिकाऊ हैं ।कॉप्सडे 2025 दो प्रमुख वैश्विक प्रयासों से भी जुड़ता है: संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच , जो प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों की समीक्षा कर रहा है, और सामाजिक विकास के लिए आगामी दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन । ये मील के पत्थर हमें याद दिलाते हैं कि सहकारी समितियाँ केवल स्थानीय समाधान नहीं हैं - वे बदलाव के लिए एक वैश्विक आंदोलन का हिस्सा हैं ।सहकारी दिवस 2025 मनाने में हमारे साथ शामिल हों , और जागरूकता बढ़ाने में मदद करें कि कैसे सहकारी समितियां बेहतर विश्व के लिए प्रगति में सहायक हो रही हैँ। इस वर्ष के आयोजन के उद्देश्य (1)जन जागरूकता बढ़ाएँ : सतत विकास में सहकारी समितियों के योगदान पर प्रकाश डालें। (2) वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना : सहकारी समितियों के लिए उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र और प्रतिष्ठानों को मजबूत करना। (3) सहायक ढांचे की वकालत करना : वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों के लिए सक्षम कानूनी और नीतिगत वातावरण के निर्माण को प्रोत्साहित करना। (4) नेतृत्व को प्रेरित करना : उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व को बढ़ावा देना और युवाओं को सहकारी आंदोलन में शामिल करना।

साथियों बात अगर हम सहकारिता को समझने की करें तो,सहकारिता आंदोलनसहकारी समितियों को ऐसे संघों और उद्यमों के रूप में स्वीकार किया गया है जिनके माध्यम से नागरिक अपने समुदाय और राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उन्नति में योगदान करते हुए अपने जीवन को प्रभावी ढंग से बेहतर बना सकते हैं। सहकारी आंदोलन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मामलों में एक विशिष्ट और प्रमुख हितधारक के रूप में भी मान्यता दी गई है ।सहकारी समितियों का खुला सदस्यता मॉडल धन सृजन और गरीबी उन्मूलन तक पहुँच प्रदान करता है। यह सदस्यों की आर्थिक भागीदारी के सहकारी सिद्धांत से उत्पन्न होता है: 'सदस्य अपनी सहकारी समिति की पूंजी में समान रूप से योगदान करते हैं और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित करते हैं। क्योंकि सहकारी समितियाँ पूंजी-केंद्रित नहीं बल्कि व्यक्ति-केंद्रित होती हैं, इसलिए वे पूंजी संकेन्द्रण को न तो कायम रखती हैं और न ही बढ़ाती हैं और वे अधिक निष्पक्ष तरीके से धन वितरित करती हैं ।सहकारी समितियाँ बाहरी समानता को भी बढ़ावा देती हैं। चूँकि वे समुदाय-आधारित हैं, इसलिए वे अपने समुदायों के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं - पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक रूप से। यह प्रतिबद्धता सामुदायिक गतिविधियों के लिए उनके समर्थन,स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाने के लिए आपूर्ति के स्थानीय स्रोत और निर्णय लेने में देखी जा सकती है जो उनके समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करती है ।स्थानीय समुदाय पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, सहकारी समितियाँ अपने आर्थिक और सामाजिक मॉडल के लाभों को दुनिया के सभी लोगों तक पहुँचाने की आकांक्षा रखती हैं ।वैश्वीकरण को सहकारी आंदोलन जैसे मूल्यों के एक समूह द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए; अन्यथा, यह अधिक असमानता और अतिरेक पैदा करता है जो इसे अस्थिर बनाता है ।सहकारी आंदोलन अत्यधिक लोकतांत्रिक,स्थानीय रूप सेस्वायत्त, किन्तु अंतर्राष्ट्रीय रूप से एकीकृत है, तथा संघों और उद्यमों के संगठन का एक रूप है, जिसके तहत नागरिक स्वयं सहायता और अपने स्वयं के उत्तरदायित्व पर निर्भर रहते हैं, ताकि वे ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, जिनमें न केवल आर्थिक, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्य भी शामिल हैं, जैसे गरीबी पर काबू पाना, उत्पादक रोजगार सुनिश्चित करना और सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना।

साथियों बात कर हम 3 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सहकारिता का यह कार्यक्रम करने की करें तो, नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा सहकारिता मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारत ऑर्गेनिक्स मेला 2025 का उद्घाटन किया। भारत ऑर्गेनिक्स मेला इस बात का उदाहरण है कि कैसे सहकारी मॉडल छोटे किसानों को सशक्त बना सकता है और भारतीय घरों तकसुरक्षित जैविक भोजन पहुँचा सकता है ।एनसीओएल जैविक खेती को किसानों के साथ एक राष्ट्रीय जन आंदोलन में बदल रहा है। 19 राज्यों की 7,000 से अधिक सहकारी समितियों के साथ, भारत ऑर्गेनिक्स एक मजबूत, विश्वसनीय और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला बना रहा है जो भारत के जैविक उत्पादकों को घरेलू और वैश्विक उपभोक्ताओं से जोड़ती है। एनसीओएल का लक्ष्य अगले दशक में घरेलू जैविक बाजार में अग्रणी खिलाड़ियों में से एक बनना है और भारत के लिए किसान- स्वामित्व वाला, पारदर्शी और स्केलेबल जैविक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना जारी रखेगा।

साथियों बात अगर हम सहकारीता दिवस के इतिहास की करें तो, संक्षिप्त इतिहास सहकारी संस्था का सबसे पहला अभिलेख 14 मार्च 1761 में स्कॉटलैंड से मिलता है। 1844 में उत्तरी इंग्लैंड में कपास मिलों में काम करने वाले 28 कारीगरों के एक समूह ने पहला आधुनिक सहकारी व्यवसाय स्थापित किया। 16 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्प ए/आरईएस/47/90 में आधिकारिक तौर पर जुलाई 1995 के पहले शनिवार को पहला अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस घोषित किया। यह तिथि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना की शताब्दी को चिह्नित करने के लिए चुनी गई थी।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है सहकारिता क्षेत्र में आर्थिक सामाजिकराजनीतिक संगम हो तो सटीक सफ़लता की गारंटी, 103 वाँ अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई 2025- सहकारिता एक बेहतर दुनियाँ के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान है, वैश्विक स्तरपर सहकारी समितियों के लिए उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र और प्रतिष्ठानों को मज़बूत करना, सहयोगपूर्ण कानून, नीतिगत कार्य मील का पत्थर साबित होगा।

टाटा कर्व हुई महंगी, जानिए अब क्या है नई कीमत

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा मोटर्स ने अपनी नई कूपे-SUV Tata Curvv की कीमतों में बढ़ोतरी की है जिसके चलते यह 13000 रुपये तक महंगी हो गई है। कुछ वेरिएंट्स में 3000 रुपये की मामूली वृद्धि हुई है जबकि अन्य सभी वेरिएंट्स की कीमत में 13000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। टाटा कर्व तीन इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है दो पेट्रोल और एक डीजल।

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने अपनी नई कूपे-SUV, Tata Curvv की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इसकी कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही वेरिएंट के आधार पर अब टाटा कर्व 13,000 रुपये तक महंगी हो गई है। Curvv के साथ ही कंपनी ने Tiago, Tiago NRG और Tigor कीमतों को भी अपडेट किया है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि टाटा कर्व के किस वेरिएंट की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई है?

Tata Curvv की नई कीमतें

इसके एंट्री लेवल वेरिएंट की शुरुआती कीमत अभी भी 10 लाख रुपये है। इसके अलावा, कई वेरिएंट्स की कीमतों बदलाव किया गया है। साथ ही कई वेरिएंट की कीमतें पहले की तरह ही है। जिन वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है वो हैं- Accomplished S GDI टर्बो-पेट्रोल MT डार्क एडिशन, Accomplished S GDI टर्बो-पेट्रोल DCA डार्क एडिशन, Accomplished+ A GDI टर्बो-पेट्रोल MT डार्क एडिशन, Accomplished+ A GDI टर्बो-पेट्रोल DCA डार्क एडिशन, Smart डीजल MT, Accomplished S डीजल MT डार्क एडिशन, Accomplished S डीजल DCA डार्क एडिशन, Accomplished+ A डीजल MT डार्क एडिशन, Accomplished+ A डीजल DCA डार्क एडिशन।

इन वेरिएंट की कीमत बढ़ी

कुछ वेरिएंट्स में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसमें Creative S GDI टर्बो-पेट्रोल MT, Accomplished+ A GDI टर्बो-पेट्रोल DCA, Creative+ S GDI टर्बो-पेट्रोल MT, Creative+ S GDI टर्बो-पेट्रोल DCA, Accomplished S GDI टर्बो-पेट्रोल MT, Accomplished+ A GDI टर्बो-पेट्रोल MT, Accomplished+ A GDI टर्बो-पेट्रोल DCA वेरिएंट्स शामिल है। इनके अलावा, बाकी सभी वेरिएंट्स की कीमत में 13,000 रुपये की समान बढ़ोतरी की गई है।

Tata Curvv का इंजन

टाटा कर्व को तीन इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जाता है, जिसमें दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन है। इसका 1.2-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन 118 hp की पावर और 170 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। वहीं, 1.2-लीटर हाइपीरियन पेट्रोल इंजन 123 hp की पावर और 225 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कर्व का 1.5-लीटर डीजल इंजन 116 hp की पावर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इन तीनों ही इंजन को 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 7-स्पीड DCA (डुअल-क्लच ऑटोमैटिक) के ऑप्शन के साथ भारत में ऑफर किया जाता है।

स्कोडा ऑटो ने भारत में बनाया रेकॉर्ड; 5 लाख कारों का किया निर्माण, जानिए अबतक का कैसा रहा सफर

स्कोडा ऑटो ने भारतीय बाजार में 5 लाख कारों का उत्पादन कर लिया है। कंपनी ने 2001 में भारत में पहली स्कोडा ऑक्टेविया लॉन्च की थी। स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया के सीईओ पीयूष अरोड़ा ने कहा कि यह सिर्फ 5 लाख कारों का निर्माण नहीं बल्कि 5 लाख कनेक्शन बनाने के बारे में है। स्कोडा का लक्ष्य मेक इन इंडिया के तहत भारत की विनिर्माण ताकत को बढ़ाना है।

नई दिल्ली। Skoda ऑटो ने भारतीय बाजार में 5 लाख कारों का प्रोडक्शन करके एक नई पलब्धि हासिल की है। यह न केवल स्कोडा की ग्लोबल लेवल क्वालिटी और सुरक्षा के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है, बल्कि मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूत बनाता है। भारत में Skoda के पुणे और छत्रपति संभाजी नगर में प्लॉन्ट है। आइए जानते हैं कि भारतीय बाजार में Skoda का सफर अब तक कैसा रहा?

भारत में Skoda का सफर

साल 2001 में पहली बार भारत में Skoda Octavia को रोल आउट किया गया था। इसके बाद Laura, Superb और Kodiaq को भारतीय बाजार में उतारा गया। कंपनी की इस लिस्ट में Kushaq, Slavia और हाल ही में लॉन्च हुई Kylaq भी शामिल हो गई है। इन 5 लाख वाहनों में से करीब 70% का प्रोडक्शन पुणे प्लांट में हुआ है, जबकि बाकी छत्रपति संभाजी नगर में हुए हैं।

स्कोडा का फ्यूचर प्लान

स्कोडा ऑटो ने ग्लोबल लेवल पर 130 साल और भारत में 25 साल पूरे किए हैं। कंपनी इसका जश्न मना रहा है। इस साल कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री को भी दर्ज किया है, जिसमें 7,422 गाड़ियों को डिलीवर किया गया है। स्कोडा का लक्ष्य सरकार के ₹मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड₹ विजन के अनुरूप, घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों के लिए भारत की विनिर्माण ताकत का लाभ उठाना जारी रखना है।

महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9e अब 79kWh बैटरी के साथ, रेंज में हुआ बड़ा बदलाव!

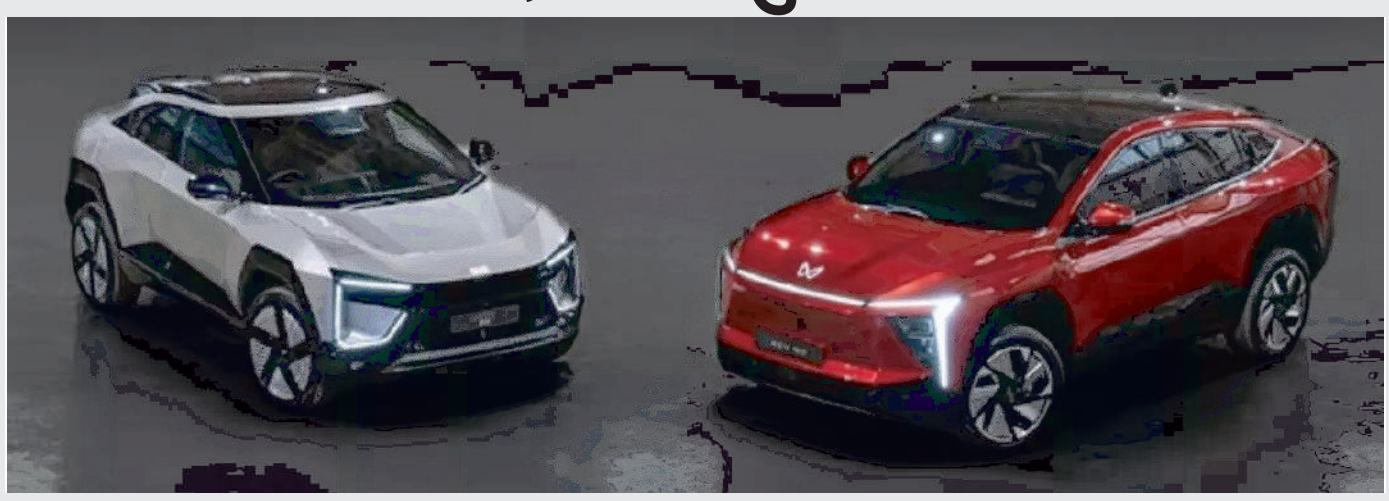

परिवहन विशेष न्यूज

महिंद्रा ऑटो ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा BE 6 और XEV 9e को 79kWh बैटरी पैक के साथ अपडेट किया है जो अब पैक टू वेरिएंट में भी उपलब्ध है। इससे ये मॉडल पहले से अधिक किफायती हो गए हैं। BE 6 Pack Two 79kWh की एक्स-शोरूम कीमत 23.50 लाख रुपये और XEV 9e Pack Two 79kWh की एक्स-शोरूम कीमत 26.50 लाख रुपये है।

नई दिल्ली। महिंद्रा ऑटो ने इलेक्ट्रिक SUVs, Mahindra BE 6 और XEV 9e को 79kWh बैटरी पैक के साथ अपडेट किया है। पहले इस बैटरी पैक को केवल टॉप-स्पेक 'पैक थ्री' वेरिएंट्स में ही मिलती थी। अब इसे पैक टू वेरिएंट्स में भी दे दिया गया है, जिसकी वजह से यह अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। इन दोनों के ही पैक टू वेरिएंट्स की इस बैटरी पैक की डिलीवरी जल्द शुरू करने वाली है। इसके साथ ही कंपनी ने ऑफर दिया है कि जिन ग्राहकों ने पहले 59kWh बैटरी वाले BE 6 और XEV 9e मॉडल बुक किए थे, वे चाहें तो नए 'पैक टू' 79kWh वेरिएंट में अपग्रेड कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि BE 6 और XEV 9e के 'पैक टू' वेरिएंट में अब 79kWh की बड़ी बैटरी मिलने के बाद नई कीमत क्या है?

कीमत और डिलीवरी की जानकारी

यह बड़ा बैटरी पैक मिलने के बाद Mahindra BE 6 Pack Two 79kWh की एक्स-शोरूम कीमत 23.50 लाख रुपये और Mahindra XEV 9e Pack Two 79kWh की एक्स-शोरूम कीमत 26.50 लाख रुपये है। इन कीमतों में चार्जर और इंस्टॉलेशन का खर्च शामिल नहीं है। 7.2kW AC फास्ट चार्जर की कीमत 50,000 रुपये और 11.2kW AC फास्ट चार्जर की कीमत 75,000 रुपये है।

रेंज और चार्जिंग कैपेसिटी

बड़ी बैटरी के साथ इन इलेक्ट्रिक SUVs की रेंज भी शानदार हो गई है, जो लंबी दूरी की यात्राओं को और आसान बनाएगी। Mahindra BE 6 79kWh बैटरी पैक के साथ ARAI प्रमाणित रेंज 682 किमी है, जबकि 59kWh यूनिट के साथ यह 556 किमी है। वहीं, XEV 9e का 79kWh बैटरी के साथ 656 किमी की सिंगल-चार्ज रेंज प्रदान करता है और 59kWh यूनिट के साथ यह 542 किमी है।

दोनों ई-एसयूवी रियर-व्हील ड्राइव मोटर्स के साथ आती हैं। 79kWh बैटरी के साथ ये 286hp की पावर देती हैं, जबकि 59kWh बैटरी के साथ ये 231hp की पावर जेनरेट करती हैं। दोनों ही वेरिएंट 380Nm का टॉर्क जनरेट करती है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

इन दोनों के ही पैक टू वेरिएंट्स कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आते हैं। इनमें एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स, फिक्स्ड ग्लास रूफ, डुअल-ज़ोन एसी, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले, डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर और रियर एसी वेंट्स मिलते हैं।

Mahindra XEV 9e और BE 6 के पैक टू वेरिएंट में 2.3-इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। दोनों में 19-इंच के पहिए दिए गए हैं। XEV 9e में अलॉय व्हील्स, तो BE 6 में एयरो कवर वाले व्हील्स दिए गए हैं।

इनमें पैसेंजर की सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS, 6 एयरबैग, EPB (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक), TPMS और सभी-व्हील डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं।

हिमाचल के शख्स ने 1 लाख की स्कूटी के लिए खरीदी 14 लाख का VIP नंबर, बताई पीछे की वजह

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के संजीव कुमार ने अपने शौक को पूरा करने के लिए एक स्कूटी के लिए 14 लाख रुपये का रजिस्ट्रेशन नंबर खरीदा। उन्होंने HP21C-0001 नंबर पाने के लिए ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया और 14 लाख की बोली लगाकर जीत हासिल की। यह नंबर एक वीआईपी नंबर है जिसके लिए अक्सर लोग मोटी रकम खर्च करते हैं।

नई दिल्ली। आपने जरूर यह सुना होगा कि शौक बड़ी चीज है, इसे हिमाचल प्रदेश के एक शख्स ने इस बात को फिर से सच साबित कर दिया है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग अपनी कार के महंगी कार केलिए खास नंबर प्लेट खरीदते हैं, लेकिन हम यहां पर आपको एक स्कूटी के बारे में बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर निवासी संजीव कुमार ने एक ऐसी स्कूटर खरीदा जिसकी कीमत तो शायद 1 लाख रुपये के आसपास होगी, लेकिन उस पर लगाया गया रजिस्ट्रेशन नंबर इतना खास है कि उसे पाने के लिए संजीव ने पूरे 14 लाख रुपये खर्च कर दिए। जी हां आपने सही पढ़ा, एक लाख रुपये की स्कूटर के लिए 14 लाख रुपये का नंबर प्लेट लिया है। इतने में तो एक लग्जरी कार आ जाएगी।

इस नंबर में क्या खास है?

संजीव कुमार मे अपने इस अनोखे शौक को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा लिया। इस नीलामी में उन्होंने HP21C-0001 नंबर हासिल करने के लिए 14 लाख रुपये की बोली लगाई और जीत गए। यह एक वीआईपी नंबर है, जिसे अक्सर लोग अपनी लग्जरी कारों या मोटरसाइकिल के लिए ऊंची कीमत पर खरीदते हैं।

कैसी रही नीलामी की प्रक्रिया?

ट्रांसपोर्ट विभाग की इस ऑनलाइन नीलामी में केवल दो लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से दूसरे बोली लगाने वाले सोलन जिले से थे, जिन्होंने 13.5 लाख रुपये की बोली लगाई थी, लेकिन संजीव कुमार ने 14 लाख रुपये की बोली लगाकर यह खास नंबर अपने नाम कर लिया।

नीलामी की रकम किसे मिलेगी?

इस नीलामी से मिली 14 लाख रुपये की पूरी रकम सीधे राज्य सरकार के खजाने में जाएगी। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह अभी तक हिमाचल प्रदेश में दोपहिया वाहनों के नंबर प्लेट के लिए की गई सबसे बड़ी नीलामी है। इससे पहले किसी भी नंबर के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं मिली थी।

फास्टैग वार्षिक पास 15 अगस्त से होगा शुरू, जानें जरूरी सवालों के जवाब

नितिन गडकरी के पास FASTag वार्षिक पास है को 15 अगस्त को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह पास निजी वाहनों के लिए है और टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को बचाएगा। यह नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के चुनिंदा प्लाजा पर एक साल या 200 ट्रिप के लिए मान्य होगा। इसे राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लिकेशन और NHAI की वेबसाइट से एक्टिवेट किया जा सकता है।

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की है कि फास्टैग सलाना पास (FASTag Annual Pass) को 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। इस नए पास को निजी वाहनों के लिए लेकर आया गया है। इससे उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, जो अक्सर टोल प्लाजा से गुजरते हैं। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी और टोल प्लाजा पर लगने वाला समय भी बचेगा। यह नेशनल हाईवे (NH) और नेशनल एक्सप्रेसवे (NE) के चुनिंदा फी प्लाजा पर एक साल या 200 ट्रिप के लिए मान्य होगा। इसमें प्रति-ट्रिप कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार की तरफ से इसको लेकर सभी जानकारी को जारी किया जा चुका है, उसके बाद भी कई लोगों को इसे समझने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको FASTag एनुअल पास से जुड़े कुछ सवालों के जवाब बता रहे हैं। आइए इन सवालों के जवाब को विस्तार में देखते हैं।

FASTag Annual Pass से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब

सवालः FASTag एनुअल पास कहां से एक्टिव किया जा सकता है?

जवाबः एनुअल पास को केवल राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लिकेशन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की वेबसाइट पर जाकर एक्टिव किया जा सकता है।

सवालः FASTag एनुअल पास को कैसे एक्टिव किया जा सकता है?

जवाबः एनुअल पास को वाहन और संबंधित FASTag की योग्यता की पुष्टि के बाद ही एक्टिवेट किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद यूजर्स को वर्ष 2025-26 के लिए 3,000 रुपये का भुगतान राजमार्गयात्रा मोबाइल एप्लिकेशन या NHAI वेबसाइट के जरिए करना होगा। भुगतान करने के बाद यह पास रजिस्टर्ड FASTag पर दो घंटे के भीतर एक्टिवेट हो जाएगा।

सवालः मेरे पास पहले से ही FASTag है, तो क्या मुझे एनुअल पास के लिए नया खरीदना पड़ेगा?

जवाबः अगर आपके पास पहले से ही FASTag है, तो आपको नया एनुअल पास खरीदने की जरूरत नहीं है। इसे आपके मौजूदा FASTag पर ही एक्टिवेट किया जा सकता है। बस आपको यह देखना होगा कि आपका FASTag वाहन की विंडशील्ड पर सही से लगा हुआ हो। इसके साथ ही वैध वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) से जुड़ा हो और ब्लैकलिस्टेड न हो।

सवालः FASTag एनुअल पास कितने समय के लिए मान्य रहेगा?

जवाबः इसके एक्टिवेशन की तारीख से एक साल या 200 ट्रिप, इसमें से पहले हो जाए तक के लिए मान्य रहेगा। जब एक बार एनुअल पास 200 ट्रिप या एक साल पूरा कर लेता है, तो यह अपने आप एक नियमित FASTag में बदल जाएगा। इसके बाद यूजर को इसे फिर से एक्टिव करना पड़ेगा।

सवालः क्या FASTag एनुअल पास को किसी दूसरे वाहन को ट्रांसफर किया जा सकता है?

जवाबः इस पास को किसी दूसरे वाहन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। यह केवल उसी वाहन के लिए मान्य होगा, जिस पर FASTag लगा है और पंजीकृत है। अगर कोई यूजर इसे किसी दूसरे वाहन पर इस्तेमाल करता है, तो फिर इसे निष्क्रिय (Inactive) कर दिया जाएगा।

सवालः अगर मेरा FASTag चेसिस नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्टर है, तो क्या मुझे एनुअल पास मिल सकता है?

जवाबः जिन फास्टैग को केवल चेसिस नंबर के साथ रजिस्टर किया गया है, उनके लिए एनुअल पास जारी नहीं किया जा सकता है। एनुअल पास को एक्टिवेट करने के लिए यूजर्स को VRN अपडेट करना पड़ेगा।

सवालः FASTag एनुअल पास के तहत एक सिंगल ट्रिप क्या है?

जवाबः अगर आप पॉइंट-आधारित फी प्लाजा से गुजरते हैं, तो हर बार पार करने पर एक ट्रिप गिना जाएगा। अगर आप राउंड ट्रिप (आना और जाना) को दो ट्रिप गिना जाएगा।

सवालः क्या FASTag एनुअल पास जरूरी है? अगर कोई इस पास के बिना सफर करता है, तो क्या होगा?

जवाबः एनुअल पास अनिवार्य नहीं है। मौजूदा FASTag सिस्टम पहले की तरह ही काम करती रहेगी। अगर कोई वाहन चालक एनुअल पास नहीं लेता है, तो वह नियमित लेनदेन के लिए अपने FASTag का इस्तेमाल जारी रख सकता है।

कक्षाओं में बहुभाषावाद सीखने के परिणामों को बढ़ाएगा

विजय गर्ग

भारत में प्राथमिक स्कूलों में नामांकित 30% से अधिक बच्चों को मध्यम से गंभीर सीखने के नुकसान का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें एक ऐसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है जिसे वे पहली बार स्कूल में शामिल होने पर नहीं बोलते या समझते हैं। इनमें दूरस्थ बस्तियों में आदिवासी समुदायों से संबंधित बच्चे शामिल हैं; अंतर-राज्य सीमा क्षेत्रों में बच्चे; मौसमी प्रवासियों सहित प्रवासी मजदूरों के बच्चे; जो बच्चे ऐसी भाषाएं बोलते हैं जिन्हें स्कूल में उपयोग की जाने वाली मानक भाषा का 'बोलियाँ' माना जाता है, लेकिन वे अलग हैं (उदाहरण के लिए बघेली, वागड़ी, बुंदेली बोलने वाले बच्चे जो हिंदी के माध्यम से पढ़ते हैं), और निश्चित रूप से, वे बच्चे जो घर पर भाषा के समर्थन के वातावरण के बिना अंग्रेजी-माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं।

स्कूलों में सीखना भाषा का उपयोग करके होता है, चाहे वह बच्चे बात कर रहे हों, सुन रहे हों, सोच रहे हों, अन्य बच्चों के साथ सहयोग कर रहे हों, पढ़ रहे हों या लिख रहे हों। अनुसंधान से पता चलता है कि एक परिचित भाषा के माध्यम से सीखना जिसे बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है जो शुरुआती सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतिरिक्त भाषाओं के सीखने का समर्थन करता है, कक्षाओं को अधिक सक्रिय और शिक्षार्थी केंद्रित बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप सभी विषयों में बेहतर समझ और सीखने का परिणाम होता है, और रचनात्मकता, अभिव्यक्ति, उच्च क्रम सोच और तर्क को बढ़ावा देता है।

अपनेपन की भावना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द फाउंडेशनल स्टेज (एनसीएफ-एफएस) 2023 प्रारंभिक सीखने के चरण में बच्चों की पहली भाषा या सबसे परिचित भाषा के उपयोग पर जोर देती है। छात्रों को समय के साथ क्रमिक रूप से दूसरी और तीसरी भाषा के संपर्क में लाया जा सकता है। एनईपी कम उम्र के बच्चों के लिए कई भाषाओं के प्राकृतिक संपर्क को भी बढ़ावा देता है क्योंकि बच्चे आसानी से मौखिक भाषा प्राप्त कर सकते हैं।

एनईपी और एनसीएफ ने बहुभाषावाद के गुणों और कक्षा में इसके उपयोग की सराहना की। हालांकि, भारत में जटिल भाषा स्थितियों को देखते हुए, इन नीतिगत योगों को लागू करना आसान नहीं है। इसके अलावा, उन भाषाओं के बारे में बहुत कम विश्वसनीय डेटा उपलब्ध है जिन्हें बच्चे समझते हैं और बोलते हैं जब वे पहली बार 5 या 6 वर्ष की आयु में स्कूल में शामिल

होते हैं। भाषण पैटर्न कम दूरी पर बदल जाते हैं और कभी-कभी बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के लिए एक विशिष्ट भाषा लेबल असाइन करना मुश्किल होता है क्योंकि कुछ स्थानीय / क्षेत्रीय भाषाएं उन्हें प्रभावित कर सकती हैं। एक कक्षा में भी बच्चों द्वारा बोली जाने वाली कई घरेलू भाषाएं हो सकती हैं। चीजों को और जटिल बनाने के लिए, यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 15% प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक उस भाषा को नहीं समझते हैं या बोलते हैं जो उनके स्कूलों में बच्चों के लिए सबसे अधिक परिचित है।

चूंकि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं को निर्देश का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जब कोई बच्चा ऐसी भाषा का अध्ययन कर रहा हो जिसे वह स्कूल में शामिल होने पर अच्छी तरह से समझ या बोल नहीं पाता है, तो उसकी मजबूत या परिचित भाषा को जगह दी जाती है औपचारिक शिक्षण में, कम से कम बोलते समय में। बच्चों द्वारा बहुत सारी बातचीत, उच्च-क्रम सोच कार्य और अभिव्यक्ति शुरू में बच्चों की मजबूत भाषा में हो सकती है, धीरे-धीरे MoI के रूप में उपयोग की जाने वाली भाषा के उच्च उपयोग में स्थानांतरित हो सकती है, जबकि कक्षा से बच्चों की परिचित भाषा को कभी नहीं हटाया जा सकता है।

उन रणनीतियों में से एक जो स्कूली शिक्षा के शुरुआती वर्षों में उन स्थितियों में सबसे अच्छा काम करती हैं जहां बच्चे द्विभाषी उभर रहे हैं, धीरे-धीरे एक कम परिचित भाषा सीख रहे हैं, शिक्षक और बच्चों के लिए उन भाषाओं के मिश्रण का उपयोग करना है जो किसी भी समय बच्चों की भाषा प्रदर्शनों की सूची के लिए सबसे उपयुक्त हैं। समय। इससे बच्चों को बेहतर तरीके से समझने, खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने और अपने भावनात्मक समायोजन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी जो बेहतर सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षण के लिए इस तरह के दृष्टिकोण के लिए शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक मजबूत बहुभाषी जागरूकता के निर्माण की आवश्यकता होती है जो दो या अधिक भाषाओं के एक साथ विकास को बढ़ावा देता है।

तीन भाषाएं सीखना जबकि सामाजिक बहुभाषावाद भारत में आदर्श है जहां ज्यादातर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में दो या दो से अधिक भाषाओं (या मिश्रित रूप में) का उपयोग करते हैं, हमारे स्कूल अक्सर शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में इस बहुभाषी वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। एनईपी 2020 निर्दिष्ट करता है कि बच्चों को उचित प्रवीणता के साथ तीन भाषाओं को सीखना चाहिए, जिनमें से कम से कम दो मूल भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। बहुभाषी समाज को शिक्षण और सीखने के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बहुभाषी दृष्टिकोण यह भी सुनिश्चित करेगा कि बच्चे अंग्रेजी में मजबूत भाषा और साक्षरता कौशल विकसित करें जो एक मजबूत आकांक्षा है। शिक्षा के लिए बहुभाषी दृष्टिकोण के कुछ मुख्य सिद्धांतों में शामिल हैं: 1. शिक्षण और सीखने के लिए औपचारिक रूप से बच्चों की सबसे परिचित भाषा का व्यापक उपयोग। 2. मातृ भाषा के समर्थन से नई या अपरिचित भाषाओं को पढ़ाया जाता है। 3. एक बहुभाषी कक्षा सभी बच्चों की भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और आपसी सम्मान को दर्शाती है। 4. सभी विषयों के लिए पाठ्यक्रम में शिक्षण और सीखने के लिए एक बहुभाषी दृष्टिकोण का उपयोग किया जाना चाहिए। 5. एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण का उद्देश्य बच्चों के स्थानीय संदर्भों और अनुभवों को कक्षा में लाना है।

तार्किक सोच और तर्क के साथ मजबूत मौखिक अभिव्यक्ति, गहरी अव्यक्त समझ के साथ धाराप्रवाह पढ़ना, और लिखित रूप में खुद को व्यक्त करने की क्षमता इस सदी में हमारे युवाओं के लिए सफलता के मूल में कौशल है। इसके लिए हमारे देश में भाषा शिक्षण प्रथाओं की अधिकता की आवश्यकता होगी और इस सुधार का केंद्र शिक्षा के लिए एक बहुभाषी दृष्टिकोण होना चाहिए।

उच्च शिक्षा: विकास, चुनौतियां और आगे सड़क

विजय गर्ग

भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र महत्वपूर्ण विकास, शैक्षणिक कार्यक्रम के विविधीकरण और हाइब्रिड लर्निंग मॉडल के उदय द्वारा चिह्नित एक गतिशील परिवर्तन से गुजर रहा है। क्षेत्रीय राजस्व में 14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षार्थी की अपेक्षाओं, तकनीकी प्रगति और नीतिगत बदलावों को बदलकर गति दी जा रही है, जो वर्तमान में 28 प्रतिशत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में अगले दशक में इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रावधान है-एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो संरचनात्मक सुधार और अभिनव वितरण तंत्र दोनों की मांग करता है।

उच्च शिक्षा परिदृश्य को आकार देने वाली एक प्रमुख प्रवृत्ति पारंपरिक, सिलोएड विषयों से उद्योग-संरेखित, बहु-विषयक कार्यक्रमों में बदलाव है। देश भर के संस्थान उभरते डोमेन जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, फिनटेक, टिकाऊ विकास और डिजिटल मार्केटिंग में पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हाइब्रिड लर्निंग मॉडल के उदय - ऑनलाइन और ऑफलाइन घटकों के संयोजन - ने पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल प्लेटफार्मों के 2020 के बाद के त्वरण ने दूरस्थ और अल्पसेवित क्षेत्रों में शिक्षा लाई है, जबकि साथ ही शहरी शिक्षार्थियों के लिए खानपान किया है जो लचीलेपन और स्वायत्तता को महत्व देते हैं। हाइब्रिड मॉडल शिक्षार्थियों की वर्तमान पीढ़ी के लिए विशेष रूप से आकर्षक हैं, जो कठोर, एक आकार-फिट-सभी कार्यक्रम के बजाय व्यक्तिगत और मॉड्यूलर सीखने की यात्रा चाहते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय नामांकन भी क्षेत्र की जीवंतता में योगदान दे रहा है। अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों के छात्र अपने सापेक्ष सामर्थ्य, गुणवत्ता आश्वासन और अंग्रेजी-भाषा के निर्देश के कारण उच्च शिक्षा के लिए भारत की तलाश कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से परिभाषित अकादमिक रोडमैप और विनियमित संस्थागत ढांचे के साथ, भारत एक विश्वसनीय वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में उभर रहा है।

हालांकि, तेजी से परिवर्तन ने अपने साथ नई चुनौतियां ला दी हैं। उनमें से प्रमुख उद्योग के अवरोधों के साथ तालमेल रखने के लिए निरंतर पाठ्यक्रम नवीकरण की आवश्यकता है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले। जैसे-जैसे परिवर्तन की गति तेज होती है, हर कुछ वर्षों में पाठ्यक्रम को संशोधित करने का पारंपरिक मॉडल अपर्याप्त हो गया है। स्वायत्त कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थान अब उद्योग के विशेषज्ञों के सहयोग से द्विवार्षिक पाठ्यक्रम समीक्षा जैसे तंत्र पेश कर रहे हैं।

यह फुर्तीले कोर्स अपडेट और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को शामिल करने की अनुमति देता है। विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा के दायरे में, नौकरी की तत्परता एक केंद्रीय चिंता का विषय बन गई है।

किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम की सफलता को तेजी से मापा जा रहा है कि यह छात्रों को कार्यबल के लिए कितनी अच्छी तरह से तैयार करता है। इसमें न केवल अकादमिक ज्ञान, बल्कि व्यावहारिक कौशल का एक पोर्टफोलियो, वर्तमान उपकरणों के संपर्क में और नई प्रौद्योगिकियों के लिए अनुकूलनशीलता भी शामिल है। संस्थान उद्योग के नेताओं से प्रमाणन मॉड्यूल एम्बेड करके, हाथों पर प्रशिक्षण की पेशकश करके और पहले सेमेस्टर से प्लेसमेंट की तैयारी शुरू करके इसे संबोधित कर रहे हैं। एनईपी 2020 का कार्यान्वयन बहु-विषयक शिक्षा, व्यावसायिक एकीकरण और कौशल-आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करके पिछली नीतियों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है। जबकि नीति अपनी दृष्टि में अच्छी तरह से तैयार है, इसका निष्पादन राज्यों में असमान बना हुआ है। गोद लेने की समयसीमा और पाठ्यक्रम ढांचे में भिन्नता के कारण खंडित परिणाम सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, एक ही संस्थान के भीतर छात्र राज्य-स्तरीय निर्देशों के आधार पर पूरी तरह से अलग-अलग शैक्षणिक मॉडल का पालन कर सकते हैं। सामंजस्य की यह कमी स्केलेबिलिटी और राष्ट्रीय बेंचमार्किंग में बाधा डालती है। संस्थागत भूमिकाओं को परिभाषित करने में नीति स्पष्टता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एनईपी अनुसंधान विश्वविद्यालयों, शिक्षण विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों में संस्थानों को वर्गीकृत करने की परिकल्पना करता है। इस तरह के वर्गीकरण से लक्षित विकास और धन की अनुमति मिलती है, लेकिन मानदंड और अतिव्यापी जनादेश में अस्पष्टता परिचालन अनिश्चितताओं का कारण बनी है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के नेतृत्व में कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत और चरणबद्ध दृष्टिकोण, संक्रमण को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है।

चिंता का एक और क्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण है। जैसे-जैसे छात्र अपेक्षाएं विकसित होती हैं, शिक्षकों की भूमिका ज्ञान डिस्पेंसर से सुविधाकर्ताओं और आकाओं में स्थानांतरित हो रही है। इस संक्रमण के लिए डिजिटल साक्षरता और अंतःविषय सोच से लेकर व्यक्तिगत सीखने के रास्तों के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करने की क्षमता तक दक्षताओं के एक नए सेट की आवश्यकता होती है। आगामी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा ढांचा, जो 2026 में लॉन्च करने के लिए तैयार है, इनमें से कुछ अंतरालों को संबोधित कर सकता है, लेकिन निरंतर व्यावसायिक विकास और शैक्षणिक नवाचार को प्राथमिकता देनी चाहिए। डिग्री और प्रमाणपत्र की बदलती धारणा भी ध्यान आकर्षित करती है। आज के जॉब मार्केट में, प्रदर्शनीय कौशल अक्सर औपचारिक योग्यता से अधिक होते हैं। नियोक्ता तेजी से अकादमिक टेप पर समस्या को सुलझाने की क्षमता, संचार कौशल और डिजिटल दक्षता पर जोर दे रहे हैं। यह बदलाव विशेष रूप से मीडिया, डिजाइन, आईटी और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट है। नतीजतन, संस्थानों को क्षमता को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने मूल्यांकन प्रणालियों और पाठ्यक्रम परिणामों को फिर से संगठित करना चाहिए, न कि केवल अनुपालन।

आगे जाकर, भारत में उच्च शिक्षा का भविष्य सार्थक सहयोग में निहित है। प्रासंगिकता, इंटर्नशिप, सलाह और प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को उद्योगों के साथ गहरी भागीदारी का निर्माण करना चाहिए। विशेषज्ञता, अनुकूलनशीलता और आजीवन सीखने के लिए एक प्रतिबद्धता प्रमुख विभेदक होगी। इन क्षेत्रों में निवेश करने वाले संस्थानों को तेजी से बदलती दुनिया के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए सबसे अच्छा स्थान दिया जाएगा।

मस्तिष्क संगीत के माध्यम से भावनात्मक संक्रमण को ट्रैक करता है

विजय गर्ग

नए शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क भावनात्मक बदलावों को कैसे नेविगेट करता है, संगीत को बदलते तंत्रिका पैटर्न को मैप करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि मस्तिष्क में भावनात्मक प्रतिक्रियाएं श्रोता की पूर्व भावनात्मक स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।

उदाहरण के लिए, एक उदास से पहले एक खुश धुन सुनने से मस्तिष्क उदासी को संसाधित करने का तरीका बदल जाता है, अगर तनाव पहले आया था की तुलना में। ये निष्कर्ष भावनात्मक विकारों के बीच भावनात्मक कठोरता के इलाज के लिए नई संभावनाएं खोलते हैं, यह लक्षित करके कि मस्तिष्क भावनात्मक राज्यों के बीच कैसे बदलता है।

संदर्भ मामले: पूर्व भावनात्मक राज्यों आकार कैसे मस्तिष्क नई भावनाओं के लिए प्रतिक्रिया करता है । एक उपकरण के रूप में संगीत: शोधकर्ताओं ने भावनात्मक संक्रमण को ट्रिगर करने और ट्रैक करने के लिए संगीतकार निर्मित संगीत का उपयोग किया। चिकित्सीय क्षमता: निष्कर्ष भावनात्मक कठोरता से जुड़े अवसाद और मनोदशा विकारों के लिए हस्तक्षेप को सूचित कर सकते हैं।

मानव मस्तिष्क भावनाओं को कैसे ट्रैक करता है और इन भावनाओं के बीच संक्रमण का समर्थन करता है?

एक नए eNeuro पेपर में, कोलंबिया विश्वविद्यालय के मैथ्यू सैक्स और सहयोगियों ने संदर्भ निर्भरता और भावनाओं की प्रकृति में उतार-चढ़ाव पर प्रकाश डालने के लिए मस्तिष्क

गतिविधि का आकलन करने के लिए संगीत और एक उन्नत दृष्टिकोण का उपयोग किया।

यह एक मस्तिष्क और संगीत नोट्स दिखाता है। ये निष्कर्ष बताते हैं कि तंत्रिका गतिविधि और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध किसी व्यक्ति की पिछली भावनात्मक स्थिति के संदर्भ पर निर्भर हो सकते हैं। साभार: न्यूरोसाइंस न्यूज

शोधकर्ताओं ने कंपोजर के साथ मिलकर ऐसे गाने बनाए, जिनसे अलग-अलग समय के बिंदुओं पर अलग-अलग भावनाएं पैदा हुईं। फिर उन्होंने अध्ययन प्रतिभागियों की मस्तिष्क गतिविधि का आकलन किया क्योंकि उन्होंने इन गीतों को सुना।

सैक्स एट अल। यह पता चला कि मस्तिष्क क्षेत्रों में गतिविधि के पैटर्न में परिवर्तन जो ध्वनि प्रसंस्करण और सामाजिक अनुभूति का समर्थन करते हैं, संगीत द्वारा ट्रिगर की गई विभिन्न भावनाओं के बीच संक्रमण को दर्शाते हैं।

विशेष रूप से, मस्तिष्क गतिविधि के पैटर्न में ये परिवर्तन पिछली भावनात्मक स्थिति से प्रभावित थे। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने उदास मार्ग को सुनने से पहले संगीत का एक हर्षित मार्ग सुना, तो उनके मस्तिष्क ने किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में दुखद मार्ग का अलग जवाब दिया जो पहले एक तनावपूर्ण संगीत मार्ग सुनता था।

शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि जब पिछली भावना संगीत द्वारा शुरू की गई नई भावना के समान थी, तो मस्तिष्क में भावनात्मक संक्रमण पहले समय में हुआ था।

ये निष्कर्ष बताते हैं कि तंत्रिका गतिविधि और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध किसी व्यक्ति की पिछली भावनात्मक स्थिति के संदर्भ पर निर्भर हो सकते हैं।

सैक्स कहते हैं, रहम जानते हैं कि जो लोग मूड डिसऑर्डर या डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं, वे अक्सर भावनात्मक कठोरता का प्रदर्शन करते हैं, जहां वे मूल रूप से भावनात्मक स्थिति में फंस जाते हैं.

रइस अध्ययन से पता चलता है कि शायद हम किसी को अवसाद के साथ ले जा सकते हैं, उदाहरण के लिए, और भावनात्मक कठोरता है कि उंहें एक बहुत ही नकारात्मक स्थिति में रहता है के लिए तंत्रिका मार्कर की पहचान करने के लिए विकसित दृष्टिकोण का उपयोग करें।

कांवड़ यात्रा में 'पहलगाम'

कांवड़-यात्रा 11 जुलाई से आरंभ हो रही है। इन सालों में जो सांप्रदायिक तनाव दिखा है, नफरत महसूस की है, कमोबेश 10 साल पहले ऐसा माहौल नहीं था। हालांकि हिंदू-मुसलमान भारतीय राजनीति का शाश्वत भाव रहा है, लेकिन कांवड़-यात्रा के दौरान मुसलमान भी शिव-भक्तों की खूब सेवा करते दिखाई दिए हैं। शिविर लगाए जाते रहे हैं, भोजन परोसा जाता है, मीठा पानी पिलाया जाता है, शिव-भक्तों के जख्मों की प्राथमिक चिकित्सा भी की जाती रही है। फिर ऐसा क्या हो गया कि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की तुलना पहलगाम के हत्यारे आतंकियों से करने की नौबत आ गई? उप्र और उत्तराखंड सरकारों ने आदेश जारी किए हैं कि कांवड़-यात्रा के मार्ग के ढाबे, होटल, रेस्तरां, दुकानदार, खोमचेवाले स्पष्ट नामपट्टिका लगाएंगे। लाइसेंस नंबर भी दिखाएं और पहचान-पत्र रखें। यानी स्पष्ट होना चाहिए कि ढाबे, होटल का मालिक हिंदू है अथवा मुस्लिम है! यह व्यवस्था बीते साल भी लागू की गई थी, ताकि कांवडियों की आस्था और श्रद्धा खंडित न हो। हरिद्वार और ऋषिकेश तक की अक्सर नंगे पांव की यह यात्रा हिंदुओं का बड़ा धार्मिक आयोजन है। जुलाई, 2024 में सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम आदेश के साथ सरकार के निर्देशों पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत का फैसला था कि नामपट्टिका लगाना जरूरी नहीं है। अलबत्ता यह साफ-साफ लिखा जाना चाहिए कि ढाबे में शाकाहार या मांसाहार क्या उपलब्ध है? कांवड़-यात्री अपने पर्व के अनुसार, शाकाहार वाला ढाबा चुन सकेगा। लेकिन अदालत के फैसले को ठेंगा दिखाते हुए उप्र और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों ने इस साल फिर आदेश जारी कर दिए। उसकी आड़ में हिंदू संगठनों के कुछ स्वयंभू हुड़दंगी राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर स्थित एक ढाबे की जांच के लिए आ धमके। दलीलें दी गईं कि वह ढाबा मुस्लिम का था, लेकिन बोर्ड पर लिखा था-'पंडित का शुद्ध वैष्णो ढाबा।' यानी पहचान छिपाने का अपराध किया गया था। आरोप हैं कि हुड़दंगियों ने ढाबे के कर्मचारियों की पैंट उतरवा कर यह जांचने की कोशिश की कि वे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं! विवाद यहीं से भड़का। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि इन और पहलगाम के आतंकियों में क्या फर्क है? दोनों तरह के आतंकियों ने धर्म की आड़ में कुकर्म किया।

फर्क सिर्फ इतना है कि पहलगाम के आतंकियों ने धर्म पूछ कर गोली मार दी और हिंदू पर्यटकों की हत्याएं कीं। कांवडियों के पैरोकारों ने पैंट ही उतरवाई थी। उस ढाबे पर यह घटना हुई अथवा उसे 'सांप्रदायिक मोड़' दे दिया गया, यह जांच पुलिस कर रही है। प्राथमिकी में 6 आरोपितों के नाम हैं। सभी हिंदूवादी संगठनों के बताए जा रहे हैं। इस घटना में एक स्वयंभू बाबा भी कूद पड़े हैं, जो उसी इलाके में योग-साधना सिखाते हैं। उन्होंने धमकी दी है कि यदि कोई केस बनाया गया, तो देश भर में आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। बाबा ने पैंट उतारने की घटना को फर्जी करार दिया है। यहां बेहद गंभीर सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारों की कानून-व्यवस्था बेलगाम और हिंदू दबंगइयों के हाथ है? उप्र देश का सबसे बड़ा राज्य है और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी झटका लगा था। उसके बाद भाजपा नेता ऑफ दि रिकॉर्ड कहते रहे हैं कि हम ऐसा हिंदू-मुसलमान करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। क्या वही राजनीति सामने आ रही है? बहरहाल पुलिस विशेषज्ञों का मानना है कि इलाके के ढाबों, होटलों और खोमचेवालों के नाम, पिता का नाम, मोबाइल, पता आदि का संपूर्ण डाटा 'बीट कांस्टेबल' के पास होता है। तो फिर जांच के लिए छापामारी करने को हिंदू दबंगइयों को किसने निर्देश दिए थे? हरी झंडी दिखाई थी? यह हरकत आपराधिक और दंडनीय है, लेकिन माना जाता है कि ये कथित हिंदू हुड़दंगी एक निश्चित राजनीतिक संरक्षण में पलते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे असामाजिक तत्त्वों को 'आस्तीन के सांप' करार दिया था। उप्र और उत्तराखंड में कांवड़-यात्राएं आयोजित की जाएंगी, जबकि कश्मीर में 'अमरनाथ यात्रा' शुरू हो चुकी है। उस यात्रा के दौरान प्रबंध करने वाले सभी मुसलमान होते हैं। वहां हिंदू-मुसलमान के बीच धार्मिक समभाव, सौहार्द क्यों है?

अगर आपको हमेशा रहती है थकान तो हो जाइए सावधान

विजय गर्ग

मायाल्जिक एन्सेफलोमाइलाइटिस/ क्रानिक थकान सिंड्रोम (एमई/सीएफएस) का नाम जितना जटिल है, यह बीमारी उतनी ही संवेदनशील है। इसे कभी-कभी केवल क्रानिक थकान के रूप में संदर्भित किया जाता है लेकिन थकान केवल इसके लक्षणों में से एक है। आस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं के मुताबिक, वास्तव में, एमई/ सीएफएस एक जटिल न्यूरोलाजिकल बीमारी है जो शरीर की लगभग हर प्रणाली को प्रभावित करती है। इसका नाम मांसपेशियों में दर्द (मायाल्जिया), मस्तिष्क की सूजन (एन्सेफलोमाइलाइटिस) और लंबे समय तक रहने वाली थकान को संदर्भित करता है जिसमें आराम करने से भी राहत नहीं मिलती है।

क्या है एम / सीएफएस : एमई / सीएफएस सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है लेकिन आमतौर पर ये मध्य उम्र के दौरान ज्यादा देखने को मिलती है। यह महिलाओं में पुरुषों की तुलना में दो से तीन गुना अधिक सामान्य है । इस स्थिति के दो मुख्य लक्षण हैं। एक अक्षम करने वाली दीर्घकालिक थकान जिसमें आराम से भी राहत नहीं मिलती और दूसरा शारीरिक या मानसिक प्रयास के बाद लक्षणों का बिगड़ना । इसे पोस्ट- एक्सशनल माइलेज के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि थोड़ी सी मेहनत भी लक्षणों को बहुत खराब कर सकती है। यह अलग-अलग लोगों में भिन्न-भिन्न हो सकती है। इसके लक्षणों की बात करें तो ज्यादातर लोगों में दर्द, नींद की समस्या, संज्ञानात्मक कठिनाइयां (जैसे सोचने, याद रखने और निर्णय लेने में), फ्लू जैसे लक्षण, चक्कर आना, पाचन संबंधी समस्याएं, हृदय गति में उतार-चढ़ाव और कई अन्य समस्याएं शामिल हैं। कई शोधों से यह भी पता चलता है कि यह स्थिति शरीर की ऊर्जा उत्पादन (मेटाबालिज्म), संक्रमण से लड़ने (प्रतिरक्षा प्रणाली), मांसपेशियों तक आक्सीजन पहुंचाने और रक्तचाप व हृदय गति को नियंत्रित करने (वाहिकीय प्रणाली) के तरीके को भी प्रभावित करती है।

आस्था का प्रतीक है सुलतानगंज से देवघर की कांवरयात्रा

कुमार कृष्णन

श्रावण के महीने को भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। यही कारण है कि इस महीने में महादेव की पूजा, आराधना का विशेष महत्व होता है किंतु श्रावण के महीने में बिहार और झारखंड राज्यों में भगवान शिव की पूजा कुछ अलग ही अंदाज में की जाती है।

श्रावण मास के प्रारंभ होते ही प्रत्येक वर्ष बिहार और झारखंड का पूरा क्षेत्र केसरिया वस्त्रधारी कांवरियां शिव-भक्तों की आवाजाही व 'बोल बम' के नारों से गुंजायमान हो उठता है।

कांवरिया बिहार के सुल्तानगंज से जल लेकर 110 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा तय करते हैं। सुल्तानगंज से जल लेकर नाचते-गाते बाबा बैद्यनाथ के धाम की ओर प्रस्थान करते हैं।

पूरे श्रावण मास में बिहार-झारखंड सहित बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य भागों के अलावे पड़ोसी देश नेपाल आदि से भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में कांवरियां शिव-भक्त बिहार के सुल्तानगंज (भागलपुर जिला) नामक स्थान में आते हैं और यहां से उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल अपने कांवरों में लेकर नियम-निष्ठापूर्वक खुले पांव पैदल चलकर इसे झारखंड के देवघर स्थित वैद्यनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग पर अर्पित कर अपने कष्ट-व्याधियों को दूर करने तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति की कामना करते हैं।

वैद्यनाथधाम स्थित देवघर के ऐतिहासिक विवरण का उल्लेख शिवपुराण में है।यहां के संपूर्ण जीवन के केन्द्र विन्दु बाबा वैद्यनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है।शिवपुराण में वर्णित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में इसका 'वैद्यनाथ चिताभूमि' के रूप में वर्णन है। यह मात्र संयोग नहीं है कि देवघर भी शिव की चिताभूमि के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहां माता सती का हृदय गिरा था। शिव पुराण के अनुसार यहीं पर माता के हृदय का दाह-संस्कार किया गया था। और तब बाबा बैद्यनाथ माता सती के वियोग में उसी राख में लोट-लोटकर पूरे अंग को भस्म विभूषित कर लिए थे। इसलिए भस्म का यहां विशेष महत्व है। और आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में भस्म भी दिया जाता है। मान्यता यह भी है कि इस भस्म को अपने ललाट पर लगाकर किसी भी कार्य के लिए निकले वह कार्य पूर्ण होता है। मनोवांछित फलों की प्राप्ति भस्म को अपने ललाट पर लगाने से होती है। देवघर के तीर्थ पुरोहित के श्रीनाथ महाराज के मुताबिक सावन और भादो में तीर्थ पुरोहित अपने यजमान को हवन से प्राप्त भस्म देते हैं। भगवान शिव का यह पीठ उर्जा का उदगमस्थल है, शक्ति का केन्द्र है। देवर्षि नारद ने हनुमान से बैद्यनाथधाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि यही एक मात्र स्थान है जहां शिव बिना पात्र — कुपात्र, पापी पुण्यात्मा का विचार किए सबकी कामना पूर्ण करते हैं।

बाबा वैद्यनाथ के प्रादुर्भाव की कथा भी कुछ कौतुहलपूर्ण और अनोखी नहीं है। इस लिंग की स्थापना का इतिहास यह है कि एक बार असुरराज रावण ने हिमालय पर जाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिये घोर तपस्या की और अपने सिर काट-काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिये। एक-एक करके नौ सिर चढ़ाने के बाद दसवाँ सिर भी काटने को ही था कि शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गये। उन्होंने उसके दसों सिर ज्यों-के-त्यों कर दिये और उससे वरदान माँगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने के लिये उसे ले जाने की आज्ञा माँगी। शिवजी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख देगा तो वह वहीं अचल हो जाएगा। अन्ततोगत्वा वही हुआ। रावण शिवलिंग लेकर चला पर मार्ग में एक चिताभूमि आने पर उसे लघुशंका निवृत्ति की आवश्यकता हुई। रावण उस लिंग को एक व्यक्ति को थमा लघुशंका-निवृत्ति करने चला गया। इधर उन व्यक्ति ने ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे न उखाड़ सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अँगूठा गड़ाकर लंका को चला गया। इधर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की वहीं उसी स्थान पर प्रतिस्थापना कर दी और शिव-स्तुति करते हुए वापस स्वर्ग को चले गये। जनश्रुति व लोक-मान्यता के अनुसार यह वैद्यनाथ-ज्योतिर्लिग मनोवांछित फल देने वाला है।

लंकापति रावण के द्वारा स्थापित होने के कारण ये 'रावणेश्वर वैद्यनाथ' भी कहलाते हैं। शुद्ध हृदय से पूजा करने पर ये बड़ी सहजता से प्रसन्न हो उठते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं।इस कारण मनोकामना लिंग के नाम से भी इनकी प्रसिद्धि है। बाबा वैद्यनाथ की पूजा अत्यंत सरल है। निर्मल हृदय फूल और बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर उत्तरवाहिनी गंगा का जल अर्पित करो और बाबा प्रसन्न। तभी तो श्रावण मास के आते ही भक्तगण देश के कोने-कोने से कातर भाव से यहां शिवपूजन हेतु खिंचे चले आते हैं। देवघर तो आधुनिक नाम है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'देवताओं का घर'। पर संस्कृत ग्रंथों में हृदपीठ, रावण वन, हरितिकी वन या वैद्यनाथ मिलता है। अघोर साधना का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण देवघर का तांत्रिक साधना के लिए कामाख्या के बाद स्थान आता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय है। फिर सुल्तानगंज में आकर गंगा उत्तरवाहिनी हो जाती जो कि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यही कारण है कि अपने इष्टदेव को प्रसन्न करने हेतु प्रति वर्ष बड़ी संख्या में कांवरियां शिव-भक्त सुल्तानगंज से जल लेकर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करने हेतु यहां आते हैं। सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर में अर्पित करने की परम्परा काफी पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम भगवान श्री रामचन्द्र ने सुल्तानगंज से जल लेकर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर अर्पित किया था और तब से ही इस परम्परा की शुरुआत हो गई जो आजतक जारी है।

सावन का महीना शुरू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिदिन हजारों शिव-भक्तों की आवाजाही सुल्तानगंज में शुरू हो जाती है। सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक के 110 किमी के क्षेत्र में बिहार राज्य के भागलपुर, मुंगेर व बांका जिलों के तथा झारखंड राज्य के देवघर व दुमका जिलों के क्षेत्र पड़ते हैं। पूरे श्रावण मास में बिहार-झारखंड की राज्य सरकारें और संबंधित जिला प्रशासन दिन-रात शिव भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा, आवासन, पेयजल, चिकित्सा, परिवहन आदि की व्यवस्था में लगी रहती हैं। पूरे 110 किमी लम्बे कांवरियां मार्ग पर भक्ति की डोर में बंधे श्रद्धालुओं की अटूट श्रृंखला निरंतर चलायमान रहती जो लोक-आस्था के महामेले का स्वरूप धारण कर लेता है जो अपने आप में अनूठा है।

सुल्तानगंज आकर भक्तगण सर्वप्रथम यहां की उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने के बाद अपने कांवरों की साज-सज्जा करते हैं। फिर कांवर की पूजा कर अजगैबीनाथ महादेव के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात अपने कंधे पर कांवर लेकर 'बोल बम' और हर-हर महादेव का उद्घोष करते हुए देवघर की ओर प्रस्थान करते हैं। शिवभक्ति से ओतप्रोत इन कांवरियां श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिलता है।

सुल्तानगंज से चलने के बाद 110 किमी के मार्ग में बिहार के भागलपुर, मुंगेर और बांका जिलों के असरगंज, कुमरसार, जिलेबिया, अबरखा, इनारावरण और गोड़ियारी नामक स्थान पड़ते हैं। इसके बाद वे पहाड़ी गोड़ियारी नदी पार कर झारखंड की सीमा में प्रवेश करते हैं जहां से देवघर की दूरी 17 किमी है। देवघर स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर गंगा के पवित्र जल के अर्पण के बाद भक्तों की कांवर यात्रा पूरी होती है। सामान्यतः भक्तगण तीन से चार दिनों में देवघर की पैदल-यात्रा तय करते हैं। ऐसे यात्री रास्ते में विश्राम करते हुए चलते हैं पर कुछ लोग अनवरत दौड़ लगाते हुए चौबीस घंटे में यह दूरी तय करते हैं जो 'डाक बम' कहलाते हैं।

प्रत्येक वर्ष बिहार और झारखंड के क्षेत्र में लगनेवाले यह महामेला सिर्फ भक्ति व श्रद्धा का धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं वरन् यह हमें शहरों के शोरगुल तथा प्रदूषण से दूर कुछ पल प्रकृति के साहचर्य में गूजारने का मौका भी देता है, जो हममें एक नयी ताजगी और ऊर्जा भर देता है। सुल्तानगंज की पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा से प्रारंभ होनेवाली यह यात्रा देवघर की शिव गंगा में जाकर पूर्ण होती है जिसके बीच मार्ग में बाग-बगीचे, हरे-भरे खेत व मैदान, पर्वत-पहाड़, नदी-नाले, पशु-पक्षी सभी मिलते हैं। बीच-बीच में सावन की रिमझिम फूहारें। श्रावणी मेले की कांवर यात्रा में जहां एक ओर मन को एक अपूर्व भक्तिमिश्रित शांति मिलती है, वहीं तन में एक नयी ऊर्जा का संचार हो जाता है जो इसमें शरीक होकर ही महसूस किया जा सकता है।

भारत के विश्व 'प्रथम' कीर्तिमान

विवेक रंजन श्रीवास्तव

भारत की रचनात्मकता, धैर्य, वैज्ञानिक सोच, साहस, खेल उत्साह और संरचना के कीर्तिमान विश्व में भारत की शक्ति दर्शाते हैं। यह वह भारत है जो पुरातन से भविष्य तक की अपनी यात्रा में संयम, समर्पण और समृद्धि से आगे बढ़ रहा है।

ये कीर्तिमान केवल संरचनाओं या आयोजनों तक सीमित नहीं हैं ये विविध क्षेत्रों में समग्र भारतीय विशेषता के परिचायक हैं।

1. चिनाब रेल ब्रिज – धरती पर सबसे ऊँचा रेलवे पुल

जम्मू–कश्मीर के रियासी जिले में, यह स्टीलआर्च ब्रिज संरचना 359मीटर की ऊँचाई की है । यह एफिल टॉवर से भी ज़्यादा ऊँचा है । और दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे पुल है। इस सीमांत परियोजना का लक्ष्य कश्मीर को स्थायी रूप से रेल नेटवर्क से जोड़ना था, जिसे कई तकनीकी एवं सुरक्षात्मक चुनौतियों के बावजूद सफलतापूर्वक पूरा किया गया ।

2. स्टेच्यू ऑफ यूनिटी – विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा

गुजरात के नर्मदा घाटी में, सरदार पटेल की 182मीटर ऊँची प्रतिमा भारतीय एका की विशाल प्रतीक है । द्वितीय विश्वयुद्ध की स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी से लगभग दुगुनी ऊँचाई की इस प्रतिमा को अक्टूबर 2018 में स्थापित किया गया था और यह आधुनिक भारत की एकता के प्रतीक पुरुष सरदार पटेल के प्रति भारत की कृतज्ञता का उदघोष करती है। यह देश के वैश्विक गौरव का प्रतीक है ।

3. नरेंद्र मोदी स्टेडियम – विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम

अहमदाबाद स्थित यह स्टेडियम 1.32 लाख दर्शकों को अपने भीतर समेट सकता है। यहाँ 11 पिचें, एडवांस सुविधाएं और विशाल दर्शक क्षमता है । जो इसे दर्शकों की उत्सुकता और भव्य उत्सव का स्थल बनाती हैं।

4. महा कुंभ मेला – दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मानव समागम

2025 के प्रयाग कुंभ में करीब 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यह आयोजन केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, अस्थायी शहर नियोजन, सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता के लिए विश्व में मिसाल बन चुका है।

5. नागपुर मेट्रो – विश्व का सबसे लंबा डबलडेकर वायाडक्ट

तीन स्तरीय– रोड, फ्लाईओवर, व मेट्रो ट्रेन संचालन – यह 3.14किमी लंबा वायाडक्ट आर्केड इंजीनियरिंग की मिसाल बन गया है, जिसे गिनीज रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है।

6. मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) – भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल

"अटल सेतु" नाम से प्रसिद्ध, है। 21.8किमी लंबे मार्ग ने मुंबई की यातायात सुविधा और रणनीतिक कनेक्टिविटी को नये आयाम दिए है।

7. बोगीबील ब्रिज – भारत का सबसे बड़ा रेलसड़क पुल

असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.94किमी तक फैला यह पुल पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवाजाही को निरंतर बनाए रखने वाला एक महत्वपूर्ण पुल है।

8. सुदर्शन सेतु – सबसे लंबा केबलस्टे होल्डर पुल

गुजरात में स्थित, यह 2.32किमी केबलस्टेयड पुल तीर्थयात्रियों के लिए रास्ता आसान करने वाला तकनीकी चमत्कार है।

9. सुदर्शन पटनायक – विश्व के सबसे ऊँचे सैंड कैसल के निर्माता

पुरी समुद्र तट पर बना 14.63मीटर ऊँचा रेत महल गिनीज के रिकॉर्ड में दर्ज है और भारतीय रेत कला को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करता है।

10. शितल महाजन – पहली भारतीय महिला स्काईडाइवर है जो अंटार्कटिका और ध्रुवों पर स्काईडाइव कर चुकीं हैं

शितल महाजन ने वहां फ्रीफॉल जंप के साथ साहसिक उड़ान की, और इस दौरान 8 विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। उनके साहस ने "हिम्मत" की मिसाल कायम की है।

11. सत्विक्षैराज रँकिरेड्डी और चिराग शेठी – सबसे तेज़ बैडमिंटन स्मैश

565किमी प्रति घंटा की रफ्तार के साथ उन्होंने बैडमिंटन की दुनिया में सर्वाधिक तेज़ स्मैश किया ।यह भारतीय खेलों की तेज़ी और तकनीकी उन्नति का प्रमाण है।

12. देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप (DOT) – भारत की सबसे बड़ी दूरबीन

3.6मीटर व्यास की यह दुरबीन उत्तराखंड में खगोल विज्ञान की दिशा में भारत की वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ा रही है।

13. चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग – भारत बना दुनिया में पहला देश

2023 में Chandrayaan3 मिशन के ज़रिये भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना। यह न केवल ISRO की वैज्ञानिक विजय थी, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका का प्रतीक बनी। यह क्षेत्र तकनीकी रूप से अत्यंत जटिल है और कभी किसी देश ने वहां लैंडिंग नहीं की थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रिकॉर्ड्स केवल ओलंपिक में ही नहीं बनते, जीवन के हर क्षेत्र में भारत नए नए कीर्तिमान बना रहा है।

भारतीय भाषाओं का डिजिटल संरक्षण: तकनीक से संस्कृति की रक्षा

[भाषा बचाओ, विरासत बचाओ: तकनीक से जुड़ती जड़ों की कहानी]

भारत की आत्मा उसकी भाषाओं में बसती है—हिन्दी की मिठास, तमिल की प्राचीनता, बंगाली की काव्यात्मकता, मराठी की गहराई, और सैकड़ों जनजातीय बोलियों की अनछुई कहानियाँ। ये भाषाएँ केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि संस्कृति, इतिहास, और पहचान का जीवंत दस्तावेज हैं। लेकिन डिजिटल युग की तेज रफ्तार और अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व ने इन भाषाओं को हाशिए पर धकेल दिया है। संथाली, भोजपुरी, मैथिली जैसी भाषाएँ विलुप्ति के कगार पर खड़ी हैं, और उनके साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी खामोश हो रही है। फिर भी, जहाँ चुनौतियाँ हैं, वहाँ आशा की किरण भी है। डिजिटल तकनीक, जो कभी इन भाषाओं के लिए खतरा मानी गई, आज उनकी रक्षा का सबसे शक्तिशाली हथियार बन रही है।

डिजिटल युग ने भारतीय भाषाओं के लिए एक नया द्वार खोला है। इंटरनेट की सर्वव्यापकता, स्मार्टफोन्स की सुलभता, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने भाषाई बाधाओं को तोड़ दिया है। आज, यूनिकोड कीबोर्ड्स ने हिंदी, तेलुगु, या कन्नड़ में टाइपिंग को सहज बना दिया है। सोशल मीडिया ने क्षेत्रीय भाषाओं को वैश्विक मंच दिया है। मिसाल के तौर पर, यूट्यूब पर मलयालम लोकगीतों के चैनल्स को लाखों लोग देख रहे हैं, जबकि ट्विटर पर मराठी कविताएँ वायरल हो रही हैं। गूगल ट्रांसलेट और भारत सरकार का 'भाषिणी' मंच वास्तविक समय में अनुवाद और वॉयस-टू-टेक्स्ट सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं, जिससे असमिया, मणिपुरी, या कोंकणी जैसी भाषाएँ डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बना रही हैं। यह तकनीकी क्रांति केवल भाषाओं को संरक्षित नहीं कर रही, बल्कि उन्हें नई पीढ़ी के लिए आकर्षक और प्रासंगिक बना रही है। विदेशों में बसे भारतीय समुदाय, जैसे अमेरिका में तमिल या कनाडा में पंजाबी डायस्पोरा, इन डिजिटल संसाधनों के जरिए अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं।

लेकिन यह यात्रा बिना रुकावटों के नहीं है। भारत में 700 से अधिक भाषाएँ और बोलियाँ हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में इनमें से अधिकांश का प्रतिनिधित्व नगण्य है। जनजातीय भाषाएँ, जैसे गोंडी, मुंडारी, या भोटिया, ऑनलाइन शब्दकोशों, साहित्य, या कंटेंट से वंचित हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लगभग 200 भाषाएँ विलुप्ति के खतरे में हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, इस चुनौती को और जटिल बनाती है। इंटरनेट की पहुँच, जो शहरी भारत में आम है, गाँवों में अभी भी सीमित है। इसके अलावा, छोटी भाषाओं में तकनीकी संसाधनों का अभाव एक बड़ी बाधा है। उदाहरण के लिए, संथाली, जो एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा वाली भाषा है, में डिजिटल कंटेंट लगभग न के बराबर है। सामाजिक धारणाएँ भी आड़े आती हैं—कई समुदायों में क्षेत्रीय भाषाएँ बोलना 'पिछड़ा' माना जाता है, और युवा अंग्रेजी को तरजीह देते हैं। यह एक विडंबना है कि हम अपनी भाषाओं को खोने के कगार पर हैं, क्योंकि हमने उन्हें डिजिटल युग में अपनाने में देरी की।

इन चुनौतियों के बीच, कई प्रेरक प्रयास इस दिशा में रोशनी की किरण बन रहे हैं। भारत सरकार की 'भारत भाषा' पहल भारतीय भाषाओं में डिजिटल कंटेंट को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत ऑनलाइन शब्दकोश, डिजिटल पुस्तकालय, और भाषा-आधारित ऐप्स विकसित किए जा रहे हैं। गैर-सरकारी संगठन और स्टार्टअप्स भी इस क्षेत्र में क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। चेन्नई का एक स्टार्टअप, 'तमिल नादु', पारंपरिक तमिल व्यंजनों और औषधीय ज्ञान को डिजिटल आर्काइव में संरक्षित कर रहा है। कोलकाता में 'लोक भाषा' नामक एक पहल बंगाली और उड़िया लोककथाओं को ऑडियोबुक और ई-बुक्स के रूप में ला रही है। व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग इस क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। बिहार के एक युवा, राकेश कुमार, मैथिली में ब्लॉग और यूट्यूब वीडियो बनाकर इस भाषा को नई पीढ़ी तक पहुँचा रहे हैं। उनकी वीडियो सीरीज, जिसमें मैथिली लोकगीतों को आधुनिक संगीत के साथ प्रस्तुत किया गया है, ने लाखों दर्शकों का ध्यान खींचा है। ये प्रयास दर्शाते हैं कि डिजिटल संरक्षण केवल तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है।

क्राउडसोर्सिंग और सामुदायिक भागीदारी ने भी इस क्षेत्र में नया जोश भरा है। विकिपीडिया ने तमिल, मलयालम, और बंगाली जैसे भाषाओं में लाखों लेख प्रकाशित किए हैं, जो समुदाय के स्वयंसेवकों की मेहनत का नतीजा है। 'भाषिणी' जैसे मंच क्षेत्रीय भाषाओं में वॉयस असिस्टेंट और अनुवाद टूल्स प्रदान कर रहे हैं, जिससे डिजिटल उपकरणों का उपयोग इन भाषाओं में आसान हो रहा है। उदाहरण के लिए, एक किसान अब तेलुगु में अपने स्मार्टफोन से मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकता है, जबकि एक छात्र मराठी में ऑनलाइन पाठ्यक्रम पढ़ सकता है। ये छोटे-छोटे कदम भाषाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रासंगिक बनाते हैं। साथ ही, सोशल मीडिया ने क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित किया है। इंस्टाग्राम पर कन्नड़ में मेम्स बनाने वाले पेज और टिकटॉक पर भोजपुरी गानों की रील्स ने युवाओं को अपनी भाषा से जोड़ा है। यह एक ऐसी क्रांति है, जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है—जहाँ आम लोग अपनी भाषा को डिजिटल दुनिया में जीवित रख रहे हैं।

फिर भी, इस दिशा में अभी लंबा रास्ता तय करना है। ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुँच बढ़ाने के लिए 'डिजिटल इंडिया' जैसी योजनाओं को और प्रभावी करना होगा। स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल साक्षरता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। निजी क्षेत्र को भी छोटी भाषाओं के लिए डिजिटल संसाधन, जैसे ऐप्स और शब्दकोश, विकसित करने में निवेश करना होगा। साथ ही, हमें सामाजिक धारणाओं को बदलने की जरूरत है—क्षेत्रीय भाषाएँ न तो पिछड़ेपन का प्रतीक हैं, न ही अंग्रेजी के सामने कमतर। यह एक सांस्कृतिक जागरूकता का सवाल है, जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका है। हमें यह समझना होगा कि अपनी भाषा को बचाना केवल शब्दों को बचाना नहीं, बल्कि अपनी पहचान, इतिहास, और भविष्य को संरक्षित करना है।

जैसे एक नदी अपने स्रोत से शुरू होकर सागर तक पहुँचती है, वैसे ही भारतीय भाषाएँ अपनी प्राचीन जड़ों से निकलकर डिजिटल युग के विशाल सागर में समा रही हैं। यह तकनीक का जादू है, जो संथाली की लोककथा को स्मार्टफोन की स्क्रीन पर ला रहा है, और तमिल की कविता को विश्व के कोने-कोने तक पहुँचा रहा है। यह एक ऐसी क्रांति है, जो न केवल हमारी भाषाओं को बचाएगी, बल्कि उन्हें नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी। हर डिजिटल क्लिक, हर ऑनलाइन पोस्ट, और हर नया ऐप हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा बचाता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस क्रांति का हिस्सा बनें—क्योंकि जब हम अपनी भाषा को बचाते हैं, तो हम भारत की आत्मा को अमर करते हैं। इस डिजिटल युग में अपनी भाषाओं को न केवल संरक्षित करें, बल्कि उन्हें एक नया जीवन दें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी उस इंद्रधनुष की छटा देख सकें, जो हमारी भाषाएँ हैं।

-प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

क्या सभ्यता अब भी युद्ध से सीखना नहीं चाहती?

[खून, आँसू और ध्वस्त बचपन: युद्ध की असली कीमत]

जब युद्ध की खबरें हवाओं में तूफान बनकर गूँजती हैं, तो वे महज हथियारों की कर्कश गर्जना, सैन्य रणनीतियों की बर्फीली चालबाजियाँ या सत्ता के क्रूर खेल की दास्तानें नहीं लातीं। वे लाती हैं—मूक आँसुओं का कराहता समंदर, टूटे सपनों की हृदयविदारक सिसकियाँ और उन अनगिनत जिंदगियों की त्रासदी, जो युद्ध की लपटों में राख बनकर बिखर जाती हैं। एक मासूम बच्चा, जो किताबों की स्याही के बजाय बारूद की गंध में खोया है, बमों की गूँज में सिहरता है। एक माँ, जो अपने लाल के लिए रोटी की जगह सिर्फ़ भय और अनिश्चितता का अंधेरा जुटा पाती है। एक बुजुर्ग, जो अपने जीवन की सारी मेहनत को मलबे के ढेर में दफ़न होते देखता है, बेबस और लाचार। इनके अनमोल दर्द की कीमत कौन चुकाएगा? युद्ध की चकाचौंध में आम इंसान की पुकार, उसकी आहट, कहीं गुम हो जाती है।

युद्ध, मानव सभ्यता का वह काला साया है, जो सदियों से उसका पीछा करता आया है। प्रथम विश्व युद्ध ने 1 करोड़ जिंदगियों को लील लिया, तो द्वितीय विश्व युद्ध ने 4-5 करोड़ मासूमों को अपनी क्रूर भेंट चढ़ा दिया। क्या यह दिल दहलाने वाली त्रासदी महज इतिहास की धूल भरी किताबों तक सिमटी है? कदापि नहीं। आज यूक्रेन-रूस संघर्ष की गूँज और इज़राइल-हमास युद्ध की चीखें हमें बार-बार उस कटु सत्य से रूबरू कराती हैं—युद्ध का सबसे बड़ा शिकार हमेशा आम इंसान होता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) की रिपोर्ट चीख-चीखकर बताती है कि फरवरी 2025 तक यूक्रेन में 10,000 से अधिक निर्दोष नागरिक मौत के आगोश में समा चुके हैं, 20,000 से ज्यादा घायल हुए हैं, और असल संख्या इससे भी कहीं अधिक भयावह हो सकती है। 1.4 करोड़ लोग अपनी जड़ों से उखड़कर बेघर हो गए, जिनमें 60 लाख शरणार्थी पड़ोसी देशों में आश्रय की तलाश में भटकने को मजबूर हैं।

गाजा की तस्वीर मानवता के माथे पर एक ऐसा दाग है, जो रक्त और आँसुओं से लिखा गया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के जनवरी 2025 के आँकड़े दिल दहलाने वाली सच्चाई उजागर करते हैं—43,000 से अधिक जिंदगियाँ युद्ध की भेंट चढ़ चुकी हैं, जिनमें 60% से ज्यादा मासूम महिलाएँ और बच्चे हैं। 23 लाख की आबादी में से 19 लाख लोग अपनी जड़ों से उखड़कर बेघर भटक रहे हैं, और 70% बुनियादी ढाँचा—घर, स्कूल, अस्पताल—मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। ये आँकड़े महज ठंडी संख्याएँ नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों की सिसकियाँ, बिखरे हुए परिवारों की चीखें और छिनी हुई जिंदगियों की कराह हैं।

युद्ध केवल जिंदगियों का काल नहीं, बल्कि सभ्यता का वह क्रूर विध्वंसक है, जो समाज के हर ताने-बाने को तार-तार कर देता है। विश्व बैंक के 2024 के अनुमान चीख-चीखकर बताते हैं कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था $150 अरब से अधिक के नुकसान के बोझ तले दब चुकी है। स्कूलों के दरवाजे बंद, अस्पताल मलबे में तब्दील, बाजारों की रौनक खामोश—आमजन की आजीविका युद्ध की भट्टी में राख हो गई। गाजा का दृश्य और भी हृदयविदारक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट के अनुसार, 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर है, जहाँ भुखमरी, बेरोजगारी और बेघरी की त्रासदी ने लाखों लोगों को जीते-जी मृत्यु के कगार पर ला खड़ा किया है। भारत के इतिहास पर नजर डालें, तो प्रथम विश्व युद्ध में 8 लाख भारतीय सैनिकों ने अपनी जान जोखिम में डाली, जिनमें 47,746 ने अपनी आहुति दी और 65,000 घायल हुए। उस दौर में आम भारतीय अकाल, भारी करों और औपनिवेशिक शोषण की चक्की में पिसता रहा। आज भी, भारत-चीन सीमा तनाव और कश्मीर में अशांति की खबरें सीमावर्ती गाँवों के लिए रोज़मर्रा का डर बनकर मंडराती हैं।

युद्ध का जहर न केवल शरीर को छलनी करता है, बल्कि मन, आत्मा और संस्कृति को भी रौंद डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की चेतावनी बताती है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में 20-30% लोग पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी) की चपेट में आते हैं, जहाँ दिमाग़ में बार-बार लौटने वाली भयावह यादें जीवन को नरक बना देती हैं। यूक्रेन में बच्चों और महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ 40% तक बढ़ चुकी हैं, जो हर रात बमों की गूँज और अपनों के खोने के दर्द में सिसकते हैं। गाजा का दृश्य और भी हृदयविदारक है—यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, 90% बच्चे मानसिक तनाव की ऐसी गिरफ्त में हैं कि उनका बचपन बमों की आवाज़ और मौत की छाया में दम तोड़ रहा है। सांस्कृतिक विनाश का घाव भी कम गहरा नहीं। सीरिया के गृहयुद्ध ने 500 से अधिक सांस्कृतिक धरोहरों को मलबे में बदल दिया, जबकि यूक्रेन में, यूनेस्को के 2024 के आँकड़ों के मुताबिक, 250 से ज्यादा सांस्कृतिक स्थल युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। ये महज पत्थर और इमारतें नहीं, बल्कि समुदायों की पहचान, इतिहास की साँसें और आने वाली पीढ़ियों का गौरव हैं, जो युद्ध की आग में स्वाहा हो रहे हैं।

यमन का गृहयुद्ध, जो 2015 से मानवता को लहूलुहान कर रहा है, 3.77 लाख जिंदगियों को निगल चुका है, जिनमें 70% मासूम नागरिक थे—वह बच्चे, माएँ और बुजुर्ग, जिनका गुनाह बस इतना था कि वे गलत समय पर गलत जगह थे। लेकिन वैश्विक मंचों पर यह त्रासदी महज ठंडे आँकड़ों का हिस्सा बनकर रह जाती है। भूख से बिलखते बच्चे, बीमारी से जूझते परिवार, और बेघर होकर सड़कों पर भटकते लोग—इनकी चीखें क्या कोई सुनता है? संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे संगठन राहत के लिए जूझते हैं, मगर उनकी कोशिशें समंदर में बूँद सरीखी हैं। गाजा में 2024 में मात्र 30% आवश्यक सहायता ही पहुँच सकी, बाकी सब युद्ध की भट्टी में जल गया। जेनेवा संधि जैसे अंतरराष्ट्रीय कानून नागरिकों की रक्षा की दुहाई देते हैं, पर इनका उल्लंघन अब रोज़मर्रा की बात हो चुकी है। ड्रोन हमले और साइबर युद्ध जैसे नए खतरे आम इंसान की जिंदगी को और भी भयावह बना रहे हैं। भारत, जो शांति का पक्षधर है और यूएन शांति मिशनों में सबसे अधिक सैनिक भेजता है, फिर भी अपने सीमावर्ती गाँवों में रहने वाले लोग युद्ध की आशंका के साये में हर साँस लेते हैं।

युद्ध की खबरें महज रणनीतियों का शोर या सत्ता का क्रूर खेल नहीं; वे उन लाखों बिखरे सपनों, टूटी जिंदगियों और मूक चीखों की गूँज हैं, जो अपने घर, आशाएँ और अपनों को खो चुके हैं। गाजा में 43,000 मौतें और यूक्रेन में 1.4 करोड़ विस्थापित लोग—ये ठंडे आँकड़े नहीं, बल्कि मानवता के माथे पर लगे वो जख्म हैं, जो हमें ललकारते हैं। आम इंसान की कराह को सुनना, उनकी हिफाज़त को सर्वोपरि रखना और युद्ध की आग को थामने के लिए ठोस कदम उठाना—यही आज का सबसे ज्वलंत कर्तव्य है। अगर हम इन बेबस आवाज़ों को अनसुना छोड़ देंगे, तो कल हमारी मानवता का भविष्य अंधेरे की गर्त में डूब जाएगा। यह सवाल हर दिल को झकझोरता है—और इसका जवाब हमारी साझा ज़िम्मेदारी में छिपा है, जो हमें आज, अभी, एकजुट होकर जवाब देना होगा।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

पैरेंटिंग 2.0: तकनीक और ममता के बीच पुल बनते माता-पिता

[डिजिटल चुनौतियों में घिरा बचपन : पथ-प्रदर्शक बनते अभिभावक]

जब एक बच्चे की मासूम आँखों में दुनिया की पहली किरण झलकती है, तो उसकी नजरें माता-पिता का चेहरा नहीं, बल्कि उनके अथाह प्यार, उनकी गर्माहट और उनकी अनंत उम्मीदों का सागर देखती हैं। यह वह पल है, जब एक नन्हा दिल धड़कना शुरू करता है, और माता-पिता का हर शब्द, हर स्पर्श, उस कोरे मन की किताब पर अमिट स्याही बनकर उतरता है। लेकिन आज का दौर वह नहीं, जहाँ केवल लोरियों की मिठास या परियों की कहानियों का जादू बच्चे का भविष्य संवार सकता है। यह युग डिजिटल चमक, सूचनाओं के तूफान और जटिल रिश्तों का है। यहाँ पेरेंटिंग अब सिर्फ़ पालन-पोषण नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है, जो बच्चों को तकनीक की चकाचौंध और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन का पाठ पढ़ाती है। यह एक अनमोल सफ़र है, जहाँ माता-पिता न केवल मार्गदर्शक, बल्कि सहयात्री बनकर बच्चों के साथ कदम मिलाते हैं—सीखते, समझते और एक नई दुनिया को गढ़ते हुए।

आज के बच्चे डिजिटल युग के सच्चे सिपाही हैं, जिनका जन्म ही स्क्रीनों की चमक और सूचनाओं के सैलाब के बीच हुआ है। यूनिसेफ इंडिया (2023) के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 6-14 वर्ष के 71% बच्चे रोज़ाना स्मार्टफोन से जुड़े रहते हैं, औसतन 3-4 घंटे स्क्रीन की दुनिया में खोए रहते हैं। यूट्यूब उनकी पाठशाला है, सोशल मीडिया उनका मंच, और वर्चुअल दुनिया उनकी पहचान का आईना। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे छुपा है एक अदृश्य खतरा—साइबरबुलिंग, ऑनलाइन शोषण, और स्क्रीन की लत का जाल। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन (एनसीबीआई, 2024) के शोध के अनुसार, 10-18 वर्ष के 28% किशोरों ने ऑनलाइन उत्पीड़न का दंश झेला है, और 35% स्क्रीन की अतिशयता से तनाव और चिंता के शिकार हुए हैं। ऐसे में माता-पिता की भूमिका अब केवल नियमों की चौकीदारी तक सीमित नहीं। उन्हें एक भावनात्मक पथप्रदर्शक बनना है—जो स्क्रीन की ठंडी चमक के पीछे छुपे बच्चे के डर, असुरक्षा और अनकहे सपनों को न केवल समझे, बल्कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर एक सुरक्षित और प्रेरणादायक भविष्य का निर्माण करे।

पेरेंटिंग अब आदेशों का शोर नहीं, बल्कि संवाद का सौम्य संगीत है। वह दौर लद गया, जब डाँट और नसीहत से बच्चे का रास्ता बन जाता था। आज का बच्चा भरोसे की गर्माहट और खुले दिल की तलाश में है। प्यू रिसर्च सेंटर (2024) के एक सर्वे में 62% किशोरों ने खुलासा किया कि वे अपने माता-पिता के साथ दिल खोलकर बात करना चाहते हैं, मगर केवल 29% को लगता है कि उनकी भावनाओं को सही मायने में समझा जाता है। यह आँकड़ा एक गहरी सच्चाई को उघाड़ता है—बच्चों को सुनने और समझने की ज़रूरत अब पहले से कहीं ज़्यादा है। माता-पिता को हर सवाल का जवाब थोपने के बजाय, बच्चों को सवाल उठाने की हिम्मत देनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा सोशल मीडिया के किसी ट्रेंड के पीछे भागना चाहता है, तो उसे डाँटने के बजाय, प्यार से समझाना होगा कि वह ट्रेंड क्यों भटकाने वाला हो सकता है। यह प्रक्रिया न सिर्फ़ बच्चे की तार्किक सोच को जागृत करती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी आसमान की ऊँचाइयों तक उड़ान देती है।

डिजिटल साक्षरता अब पेरेंटिंग का अभिन्न अंग है, एक ऐसी कला जो आज के युग में अपरिहार्य है। बच्चे एआई से सवाल पूछते हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म पर दोस्त बनाते हैं, और ऑनलाइन अपनी पहचान की तलाश में भटकते हैं। मगर इस चमकती वर्चुअल दुनिया में वे अक्सर अकेलेपन, तुलना के दबाव, और आत्मसम्मान की चुनौतियों के भँवर में फँस जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी (2023) के एक अध्ययन ने खुलासा किया कि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से किशोरों में आत्मसम्मान 20% तक घट जाता है। ऐसे में माता-पिता को बच्चों को न केवल डिजिटल साक्षरता, बल्कि भावनात्मक परिपक्वता का पाठ भी पढ़ाना होगा। इसका अर्थ है—ऑनलाइन सामग्री की सत्यता को परखना, साइबर सुरक्षा के गुर सिखाना, और स्क्रीन टाइम का संतुलन बनाना। माता-पिता को बच्चों की ऑनलाइन दुनिया में सहयात्री बनना होगा, खुली चर्चा के ज़रिए उनके अनुभवों को समझना होगा। मिसाल के तौर पर, अगर बच्चा यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहा है, तो माता-पिता उस कंटेंट पर बात शुरू कर सकते हैं, यह पूछते हुए कि उसने उससे क्या सीखा। यह न सिर्फ़ बच्चे की आलोचनात्मक सोच को निखारता है, बल्कि माता-पिता के साथ उनके रिश्ते को भी अटूट विश्वास की डोर से बाँधता है।

आज के माता-पिता को एक सखा की तरह होना होगा—वह साथी, जो बच्चे को न केवल चलना सिखाए, बल्कि गिरकर उठने का साहस भी दे। उन्हें हर सवाल का जवाब थोपने के बजाय, सही सवाल पूछने की कला सिखानी होगी। पेरेंटिंग अब महज़ मार्गदर्शन नहीं, बल्कि एक जीवंत संवाद है, जहाँ माता-पिता और बच्चा कंधे से कंधा मिलाकर सीखते हैं—तकनीक की रफ्तार को गले लगाते हुए, संवेदनाओं की गर्माहट को सहेजते हुए, और भविष्य को सुनहरे सपनों से संवारते हुए। ऐसे युग में, जहाँ बच्चे एक कमरे में बैठकर हजारों लोगों से जुड़ सकते हैं, यह अनिवार्य है कि वे अपने माता-पिता के साथ भावनात्मक बंधन में बंधे रहें। क्योंकि अगर माता-पिता ने उन्हें समय, समझ, और प्यार की छाँव नहीं दी, तो दुनिया का तूफान उन्हें भटकाने को तैयार बैठा है।

आज के माता-पिता को अपनी भूमिका को नए सिरे से गढ़ना होगा। वे अब केवल पालनकर्ता नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत, मार्गदर्शक और डिजिटल युग के जीवन गुरु हैं। उन्हें बच्चों को न सिर्फ़ ज्ञान की रोशनी देनी है, बल्कि संवेदना, सहिष्णुता और आत्मनियंत्रण जैसे अमूल्य रत्न भी सौंपने हैं। जब बच्चे की आँखों में यह अटूट विश्वास चमकेगा कि "मेरे माता-पिता मेरे साथ हैं, मेरे दिल को समझते हैं, और हर तूफान में मेरी ढाल हैं," तभी हम गर्व से कह सकेंगे कि हमने न केवल एक बेहतर इंसान, बल्कि एक उज्ज्वल, मानवीय युग का निर्माण किया है।

-प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

नशे की रोकथाम -एक सामूहिक जिम्मेदारी।

नशा, नाश का प्रमुख कारण है। नशे की लत परिवार के परिवार के परिवार को तहस-नहस कर देती है। नशे के कारण धन की तो बर्बादी होती ही है, मनुष्य के स्वास्थ्य को भी व्यापक नुकसान पहुंचता है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) की विश्व औषधि रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया भर में लगभग 284 मिलियन लोग नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं, यह बहुत ही चिंताजनक है। वास्तव में, देखा जाए तो नशा एक बेहद ही जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जो देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य और हमारे सामाजिक ताने बाने को लगातार क्षति पहुँचा रहा है। आज तनाव अवसाद और भागम-भाग भरी जिंदगी में युवा पीढ़ी नशे का सहारा लेकर यह समझती है कि वह नशे का सहारा लेकर अपने तनाव और अवसाद को खत्म कर सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्यों कि नशे की लत लगातार बढ़ने से व्यक्ति विशेष के निजी जीवन में अवसाद, तनाव, पारिवारिक कलह, पेशेवर अकुशलता जन्म लेती हैं। व्यक्ति को फाइनेंशियल समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य समस्याओं का तो सामना करना ही पड़ता है। नशे के शिकार व्यक्ति को समाज भी हेय दृष्टि से देखने लगता है और नशे के शिकार व्यक्ति के सामने सामाजिक सह-अस्तित्व की आपसी समझ की भी समस्याएं सामने आने लगतीं हैं। कहना चाहूंगा कि कोई भी नशा व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं, मनोदशा और समन्वय जैसे तत्वों को कहीं न कहीं अवश्य प्रभावित करता है और यह बहुत ही दुखद है कि आज विशेषकर हमारे युवा नशे की लत के ज्यादा शिकार हैं। चूँकि युवावस्था में कैरियर को लेकर एक किस्म का दबाव और तनाव रहता है। ऐसे में युवा इन समस्याओं से निपटने के लिए नशीली दवाओं का सहारा लेता है और अंततः वह अनेक समस्याओं के कुचक्र में फंस जाता है। आज वर्ष 2025 की ही यदि हम यहां बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है, और यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तकनीक और विकास में हमारा देश लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है, लेकिन नशे के कारण हमारा देश लगातार पीछे भी जा रहा है, क्यों कि युवा किसी भी देश का असली भविष्य और रीढ़ होते हैं और यदि इसी रीढ़ पर नशे का प्रहार हो रहा है,तो यह हमारी रीढ़ को कमजोर करने की बड़ी साजिश है। यह बहुत ही दुखद है कि आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से लेकर शहर तक, स्कूल-कॉलेजों से लेकर, कोचिंग सेंटरों के आसपास हर कहीं पर नशे के सौदागर अपना जाल फैलाए बैठे हैं। नशे का यह खेल मिलीभगत से चलता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब नशे का यह जाल बीड़ी-सिगरेट, भांग, तंबाकू, शराब या गांजे तक ही सीमित नहीं रहा है। सिंथेटिक नशा(सिंथेटिक कैनाबिनोइड्स और सिंथेटिक कैथिनोन्स), विभिन्न प्रकार के केमिकल नशे, कैनबिस का नशा, हेरोइन(चिट्टा), ब्राउन शुगर, कोकीन जैसे घातक पदार्थ अब भारत के युवाओं के जीवन को लगातार खोखला कर रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि भारत (हमारा देश) वर्तमान में विश्व स्तर पर तम्बाकू उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है, जहाँ अनुमानित 267 मिलियन तम्बाकू उपयोगकर्ता हैं। भारत में तम्बाकू के व्यापक उपयोग के लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें सांस्कृतिक प्रथाएँ, हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी और तम्बाकू उद्योग की आक्रामक विपणन रणनीतियाँ शामिल हैं। आज आए दिन मीडिया की सुर्खियों में हमें यह पढ़ने सुनने को मिलता रहता है कि आज पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, मणिपुर, गोवा जैसे राज्यों में तो नशे का जहर हमारे पूरे सामाजिक ताने-बाने को तहस-नहस कर चुका है। यह बहुत ही दुखद है कि आज हमारे देश के लाखों नौजवान नशे की गिरफ्त में अपनी ऊर्जा, जीवन और भविष्य गंवा रहे हैं। यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो नेशनल इंग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट (एनडीडीटी), एम्स की वर्ष 2019 की रिपोर्ट बताती है कि अकेले भारत में ही लगभग 16 करोड़ लोग शराब का नशा करते हैं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की भी है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं देश में शराब,अफीम और कैनबिस का सेवन करती हैं।संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) की विश्व औषधि रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया भर में लगभग 284 मिलियन लोग नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं। इसके अनुसार, भारत ने 2019 में विश्व भर में 7% अफीम तथा 2% हेरोइन को जब्त किया है। इतना ही नहीं भारत की 10 फीसदी से अधिक आबादी अवसाद, न्यूरोसिस और मनोविकृति सहित मानसिक विकारों से पीड़ित है। इसके साथ ही प्रत्येक 1000 में से 15 व्यक्ति नशीली दवाओं का सेवन करते हैं और प्रत्येक 1000 में से 25 लोग क्रोनिक अर्थात स्थायी शराब सेवन के शिकार हैं। भारत में मनोरोग और नशा मुक्ति बिस्तर की उपलब्धता आवश्यक संख्या का केवल 10% है। इस प्रकार, देश भर में 80% मनोरोगी और नशा की समस्या से पीड़ित रोगियों को अस्पताल की सुविधा भी मयस्सर नहीं होती। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज नशे के पीछे एक पूरा तंत्र सक्रिय है। इस तस्कर,इस माफिया, पुलिस प्रशासन और राजनीति में मिलीभगत, विदेशों से आने वाली बड़ी तस्करी की खेप। अनेक स्थानों पर तो आज नशे के एजेंट तक सक्रिय हैं,जो जहर की पुड़ियाओं को बेचते नजर आते हैं। पहले बच्चों में, युवाओं में इसकी लत विकसित की जाती है और फ्री में नशा उपलब्ध कराया जाता है और जब बच्चों को, युवाओं की नशे की आदत या लत लग जाती है तो उन्हें महंगी दरों पर खतरनाक नशा बेचा जाता है,इससे उनका करियर, पढ़ाई, धन व स्वास्थ्य को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है।कहना ग़लत नहीं होगा कि ये सब मिल कर हमारे देश को लगातार अंदर से दीमक की भांति खोखला कर रहे हैं।पाठकों को बताता चलूं कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार नशे की लत के कारण वर्ष 2021 में 10 हजार से अधिक लोगों ने अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिया, यह बहुत ही दुखद है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ नागरिकों की आवश्यकता होती है। वास्तव में देखा जाए तो एक स्वस्थ राष्ट्र का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि स्वस्थ नागरिक एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र की नींव होते हैं। स्वस्थ लोग अधिक उत्पादक होते हैं, बेहतर सामाजिक संबंध बनाते हैं और समुदाय में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं। स्वस्थ राष्ट्र आर्थिक रूप से भी मजबूत होते हैं, क्योंकि स्वस्थ लोग काम करने, कमाने और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने में सक्षम होते हैं, लेकिन जिस देश के युवा ही अस्वस्थ और नशे में हों, उस राष्ट्र की कल्पना कैसे साकार हो सकती है ? याद रखिए कि युवा ही किसी देश की असली रीढ़ होते हैं। इसलिए इस रीढ़ की रक्षा की जानी बहुत ही महत्वपूर्ण, जरूरी और आवश्यक है। आज हमारी सरकारें, विभिन्न एनजीओ, संस्थाएं, सामाजिक संगठन, स्कूल और कॉलेज नशे खिलाफ समय-समय पर विभिन्न प्रकार के 'जागृति अभियान', 'स्लोगन प्रतियोगिताएं', या 'भाषण प्रतियोगिताएं' जैसे अनेक प्रतीकात्मक कार्यक्रमों आदि का आयोजन करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे कुछ बदलता है या इसका कुछ खास असर हमारे समाज पर पड़ता है ? सच तो यह है कि महज औपचारिकताएं ही आज नशे की रोकथाम पर नजर आतीं हैं। वास्तव में आज नशे पर रोकथाम बहुत ही जरूरी है और यह तभी संभव हो सकता है जब हमारी सरकारें, हमारे एनजीओ, हमारे विभिन्न सामाजिक संगठन और हम स्वयं नशे के खिलाफ एकजुट होकर आगे आए। वास्तव में नशे पर रोकथाम के लिए मजबूत नीति, ईमानदार क्रियान्वयन और राजनीतिक इच्छाशक्ति बहुत ही जरूरी है।जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा, उपचार और पुनर्वास, और सामाजिक सहयोग भी नशे पर रोकथाम के लिए जरूरी तत्व हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम नशीली दवाओं के उपयोग के नकारात्मक प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाएं तथा सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों का उपयोग करके नशे के खिलाफ संदेश फैलाएं।नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए कानूनों को भी हमें लागू करना होगा। वास्तव में, नशीली दवाओं की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाना होगा। अंत में यही कहूंगा कि नशे की रोकथाम एक सामूहिक जिम्मेदारी है, किसी व्यक्ति विशेष, समाज विशेष या सरकार विशेष की नहीं।सच तो यह है कि इसमें सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

भोगनाडीह कांड को लेकर रांची से सरायकेला तक 22 जिलों में झामुमो का विरोध प्रदर्शन
सरायकेला में पहली बार चंपाई का पूतला झामुमो ने जलाया

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

रांची, झामुमो द्वारा भोगनाडीह कांड को लेकर राजधानी से लेकर समुचे राज्य के विभिन्न जिलों में जहां भाजपा का पुतला फूंका गया वहीं सरायकेला खरसावां जिले में पूर्व मुख्यमंत्री संप्रति विधायक सरायकेला चंपाई सोरेन का पुतला को झामुमो ने पहली बार आग के हवाले किया ।

रांची जिला के संयोजक प्रमुख मुस्ताक आलम गुरुवार को भाजपा का पुतला राजधानी में दहन किया। मौके पर झामुमो रांची जिला संयोजक प्रमुख मुस्ताक आलम ने कहा हूल दिवस के अवसर पर भोगनाडीह मे हर साल सरकारी कार्यक्रम होता है, परन्तु इस बार वहां पर भाजपा द्वारा झारखण्ड को अस्थिर करने की साजिश रची गई। वहां के भोले भाले लोगों को साड़ी और पैसे बांटकर और हथियार देकर झारखण्ड खासकर संथाल परगना को मणिपुर बनाने की साजिश की गई। इसे लेकर पूरे झारखण्ड मे रोष है जिसके विरोध में गुरुवार को पूरे चौबीसों जिलों मे पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है।

उधर सरायकेला की जमीन पर अलग झारखंड राज्य आन्दोलन को लेकर शिबू सोरेन के साथ चले नेताओं में तब सरायकेला से कृष्णा मार्डी हुआ करते थे ,पर उन्होने सूरज मंडल से टिकट लेकर जब अपनी पत्नी मोती मार्डी को जब नामांकन कराया तब चंपाई किस्मत फड़का । 90 के दशक में झामुमो के सोरेन गुट के शिबू सोरेन मैदान में इन्हें उतारा था । दोनों तीर धनुष छाप लेकर तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला, आभाष झा के सामने बिहार विधानसभा चुनाव सरायकेला सीट से लडने खड़े थे ।एक चिन्ह दो उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी झा पंद्रह मिनट तक किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाते नामांकन कक्ष में । तब तीर धनुष चिन्ह को जप्त करते हुए निर्वाचन पदाधिकारी झा एक को सेब तथा दूसरे को घंटी थमा दी थी । यह पहली मर्तबा ऐसा हुआ जब जेएमएम के साथ तीर धनुष विधानसभा चुनाव में सिम्बोल नहीं बन सका था बिहार राज्य में । जिसमें चंपाई किस्मत साथ दिया - मतगणना स्थल पर जब इस संबाद दाता ने उन्हें पौ फटने से पहले चुनाव जीत जितने का संबाद चंपाई सोरेन को सुनाया तब उन्हें यकीन हुआ ही नहीं था कि वे कृष्णा मार्डी के पत्नी को हरा चुके हैं । उसके वाद चंपाई शिबू सोरेन के प्रिय होते चले गये । यहां तक की विगत चुनाव पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री बनाये गये ।परन्तु चंपाई सोरेन अपने गलत रणनीतिकार व एक चर्चित गलत सलाह कार के कारण पार्टी से अनायास दुर किये गये । फिर दिल्ली जाकर भाजपा का कमल थमा , जिसके कारण आज उनके जमीन पर पहली बार उनका पूतला जलाते हुए उसी झामुमो के उगली पीढी को हर्षोल्लास करते देखा गया । सरायकेला जिला

मुख्यालय के गैरेज चौक में झामुमो ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन व बाबूलाल मरांडी का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ । इस अवसर पर झामुमो के समर्पित नेता जिलाध्यक्ष डॉ शुभेन्दु महतो के नेतृत्व में जिला समिति के सभी पदाधिकारी,सक्रिय कार्यकर्ता एवं समर्थकों ने एकजुट होकर भाजपा के षड्यंत्र का पुरजोर विरोध किया ।झामुमो जिला अध्यक्ष डॉ शुभेन्दु महतो ने कहा कि झारखंड की अस्मिता, शहीदों की विरासत और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भोगनाडीह में हुई घटना पूरे राज्य के लिए शर्मनाक, निंदनीय और काफ़ी गंभीर है । विपक्षी दलों खासकर भाजपा की जो भूमिका इस घटनाक्रम में रही है वह चिंता का विषय है. एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल पर इस प्रकार की घटना कराकर भाजपा ने संथाल परगना सहित समूचे झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों को शर्मसार करने का कुत्सित प्रयास किया है। भाजपा को समझना चाहिए कि सिदो-कान्हू,चांद-भैरव और फूलो-झानो किसी पार्टी विशेष के नहीं बल्कि झारखंड के हीरो के रूप में याद किए जाते हैं ।ऐसे महान सेनानियों के पावन कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किसी भी एंगल से स्वीकार्य नहीं है।

साथ ही राज्य सरकार से भोगनाडीह की घटना के उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हैं । इस कार्य क्रम में नगर के अनेक कार्यकर्ता सहित जिले के तीनों विधानसभाओं आये जेएमएम नेता , कार्यकर्ता मौजूद रहे ।

पुरी हवाई अड्डे के निर्माण को झटका, वन भूमि अधिग्रहण की मंजूरी स्थगित

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : पुरी एयरपोर्ट के निर्माण में अड़चनें आ गई हैं। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले एयरपोर्ट बनाने की अनुमति दी थी। लेकिन अब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की आपत्ति के बाद यह योजना अनिश्चितता में पड़ गई है। जबकि इसे 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया जाना था, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है।केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने विदेशी पक्षियों और ऑलिव रिडले के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वन भूमि पर निर्माण पर आपत्ति जताई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पुरी एयरपोर्ट के निर्माण की राह में रोड़े

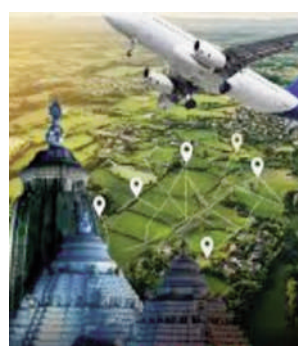

अटका दिए हैं। मंत्रालय ने आपत्ति जताई है कि एयरपोर्ट के निर्माण से पर्यावरण और जैव विविधता को खतरा होने की आशंका है। इसके लिए वन भूमि अधिग्रहण की मंजूरी को स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय 13 हजार पेड़ों के काटे जाने से नाराज है। एयरपोर्ट 471 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाना था। इसमें करीब 28 एकड़ वन भूमि और समुद्र से सटी जमीन है। इसलिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन, विदेशी पक्षियों और ऑलिव रिडले के संरक्षण को खतरा होने की आशंका जताते हुए आपत्ति जताई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 5 मई को पुरी में एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी थी। इसके लिए राज्य सरकार ने भी अपनी तत्परता दिखाई थी। इसके लिए कुल 5,0631 करोड़ रुपये का खर्च निर्धारित किया गया है।

बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाएगा; पुलिस ने 21 संदिग्धों को पकड़ा; पहचान सत्यापन जारी

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : ओडिशा में बांग्लादेशियों की पहचान का काम जारी है। गुरुवार को जंबू सामुद्रिक थाने की पुलिस ने केंद्रपाड़ा जिले के बौलाकानी पंचायत से 6 लोगों को उठाया। बताया जा रहा है कि इनमें से एक 10वीं का छात्र है। इसी तरह पुलिस ने 15 बंगाली भाषी लोगों को भी उठाया है जो केंद्रपाड़ा शहर के अलग-अलग इलाकों में घूम रहे थे और सामान बेच रहे थे।उन्हें जिला प्रशासन के पास ले जाया जा रहा है और विभिन्न पहचान व पते के प्रमाणों की जांच की जा रही है।

महाकालपाड़ा प्रखंड के बंगाली भाषी इलाकों में रहने वाले गैर-भारतीय विभिन्न माध्यमों से भारत में प्रवेश करते थे। बाद में वे अवैध आधार कार्ड बनवाकर खुद को भारतीय साबित करने की कोशिश करते थे। वे राशन कार्ड बनवाकर मतदाता पहचान पत्र में नाम दर्ज करवा लेते थे। लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा बांग्लादेशी पहचान प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार यहां छिपकर रह रहे बांग्लादेशी अपने देश लौटने की तैयारी कर रहे हैं। खबर

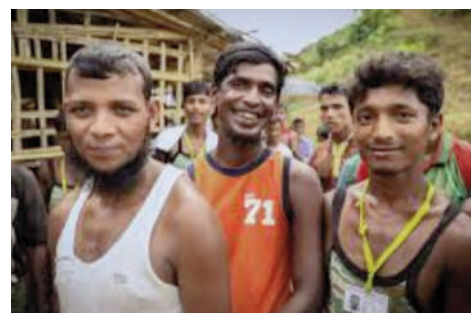

है कि कुछ ने लौटना भी शुरू कर दिया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार महाकालपाड़ा इलाके में कुछ गैर-हिंदुओं ने झींगा तालाबों की रखवाली और नावों में मछुआरे के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। इन सभी जांचों के बीच 2005 में महाकालपाड़ा, राजनगर और पट्टामुंडई प्रखंडों में आधिकारिक रूप से पहचाने गए 1649 बांग्लादेशी कहां गए?

आँचल की चुप्पी

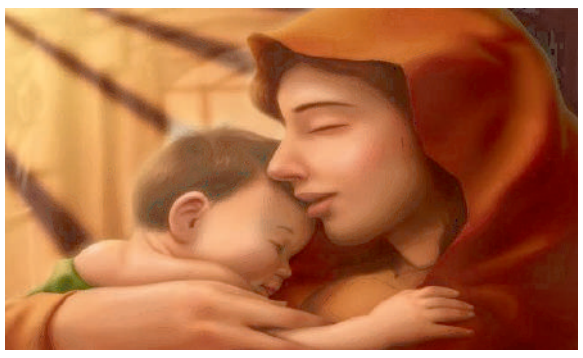

मायका छूटा, गोदी छूटी,
भाई की कंधी बोली रूठी,
सास-बहू की लोरी गूंजी,
बेटी की दुनिया पूरी झूठी।

माथे की बिंदी मांग सजाए,
थक जाए तो भी मुस्काए,
कभी ना बोले ₹अब बहुत हुआ₹,
सबका दु:ख खुद पर अपनाए।

कौन कहेगा थकी हुई है?
घर की नींव रखी हुई है!
फिर भी रिश्तों में रह गई बस,
ज़रूरत, दिलचस्पी नहीं रही
अस।

ना गोद रही, ना गोत्र, ना बाँह,
फिर भी वो निभाए चाह-राह।
बेटी थी, पर अब बहू है,
उसकी मुस्कान भी अब रुकी हुई है।

जब रोती है — आँचल से ढँक लेती,
खुद को खुद ही समझा लेती,
ना कोई पूछे, ना कोई थामे,
वो जीती है टूटे पलों के नामे।

अब वही घर उसका मंदिर है,
जहाँ वो खुद ही पुजारी भी है।
वो हँसती है, वो सहती है,
पर अब खुद में ही रहती है।

दुनिया कहे ₹बहू कितनी प्यारी₹,
किसी ने न देखी आँखों की ज्वारी,
वो बेटी से देवी बनी —
पर देवी को भी किसने सुनी?

मां काली की प्रतिमा खंडित कर कानपुर में माहौल बिगड़ने की कोशिश, दो गिरफ्तार

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां सांप्रदायिक सद्भाव के दुश्मन अराजक तत्व माहौल बिरने की कोशिश से बाद नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मां काली की प्रतिमा खंडित करके माहौल बिगड़ने की कोशिश की। मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

यह मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के भेवली गांव का है। जहां मां काली मंदिर में भोर पहर लगभग चार बजे काली प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। मंदिर के पुजारी और ग्रामीणों द्वारा दो अधेड़ व्यक्तियों को मंदिर के अंदर से ही पकड़ा गया, जिसमें से एक गैर समुदाय का है।

मौके पर पहुंची पुलिस को जानकारी देते हुए

मंदिर के पुजारी पारस ने बताया कि मध्य रात्रि दो अधेड़ व्यक्ति मंदिर के पास मोटरसाइकिल खड़ी करके अंदर चले गए और भगवान श्रीराम और अन्य देवी-देवताओं को गालियां देते हुए तोड़फोड़ कर रहे थे। आवाज सुनकर पुजारी ने अपने साथ रह रहे एक बच्चे लवकुश पुत्र रामगोपाल को गांव के अंदर भेजा।

इसके बाद शोर मचाकर अन्य लोगों को बुलवाया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तोड़फोड़ कर रहे दोनों अधेड़ व्यक्तियों को मंदिर के अंदर ही बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों शीतलाप्रसाद निषाद (50) पुत्र शत्रुघ्न निवासी 112 श्यामनगर कानपुर और शाहिद (45) निवासी बासमंडी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि दोनों ने ऐसा क्यों किया इस बारे में पूछताछ की जा रही है ,जिसके बाद निकले नतीजे के आधार पर दोनों को जेल भी भेजा जाएगा।

पूर्व विधायक अंबा एवं उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र के यहां ईडी का छापा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, सरकार के गारीमामय पद पर जनता का सेवक बने रहते हुए जमीन , खनन , ट्रान्सपोटिगं उद्योग की अतरलिप्तता पर आज हजारीबाग और बड़कागांव सहित कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। इन कारोबार से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनके करीबियों के घर ईडी ने दबिश दे दी है। आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी से जुड़े मामले में ईडी ने यह ऐक्शन लिया है। ईडी ने अंबा प्रसाद के निजी सहायक संजीव साव, मनोज दांगी, पंचम कुमार के बड़कागांव स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी की है।

सुबह-सुबह ईडी की कई टीमें झारखंड के तीन अलग-अलग शहरों में अचानक पहुंची। यहां तीनों शहरों में अलग-अलग जगहों पर टीम के सदस्य छापेमारी कर रहे हैं। मामला आरकेसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़ा हुआ है। लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। मामला अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है।

जमीन ,अवैध खनन पर कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता योगेन्द्र साव के ठिकानों पर ईडी छापे पड़ रहे हैं। इसके साथ ही अंबा के पिता और पूर्व मंत्री योगेन्द्र प्रसाद के यहां रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में छापेमारी भी है। शुक्रवार सुबह से ही योगेंद्र और उनके करीबियों के ठिकानों पर भी एक साथ छापे चली है। बड़कागांव में अंबा के निजी सहायक संजीव साव, मनोज दांगी, पंचम कुमार, मंटू सोनी के यहां भी रेड पड़ी है। मिली जानकारी के अनुसार, आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के जरिए कोयले की अवैध ढुलाई और अवैध खनन के मामले में यह छापेमारी की है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023